● वर्ष-2
● अंक-217
रायपुर, बुधवार
03 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।
समाचार पचीसा
राजनीति का जनपक्षकार

कांग्रेस लगाएगी बजरंग दल पर प्रतिबंध

घोषणापत्र में उल्लेख से भड़की भाजपा, कांग्रेस पार्टी की परिभाषा 85% कमीशन और 100% हिंदू विरोधी है

नई दिल्ली। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज आठ दिन बचे हैं। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े वादे किए हैं। एक-दूसरे के घोषणाओं पर सवाल भी उठाने लगे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को प्रजा ध्वनि नाम दिया है। वहीं, कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को संकल्प पत्र नाम दिया है। कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगाने का भी वादा किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम बजरंग दल का है।

कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक ही बात कही लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का उनका एजेंडा - एक तरह से वे बजरंग दल और पीएफआई की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि वे एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं और देशभक्त बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं।

कर्नाटक चुनाव 2023 अभियान के दौरान पीएम मोदी के लिए कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे पीएम की लोकप्रियता और सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए, वे सोचते हैं कि गंदी भाषा का उपयोग करके वे ऐसा कर सकते हैं। कम से कम खुद को संतुष्ट कर लें। लेकिन लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे...मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की परिभाषा 85% कमीशन और 100% हिंदू विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जय श्री राम साम्प्रदायिक राजनीति है। जय बजरंगबली बोलने वालों को अब जेल में डाला जाएगा। भाजपा ने दावा किया कि यह कांग्रेस द्वारा पीएफआई को बचाने का एक प्रयास है। पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने सोनिया गांधी के निर्देश पर हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। वह सिर्फ एक कल्पना है। इसलिए, रामायण पर उनका कोई महत्व नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बजरंगबली के अपमान में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उतरी है, इसे सबने देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए यह नई बात नहीं है। जय श्रीराम कहना, यह कांग्रेस पार्टी को 'कम्युनल पॉलिटिक्स' लगता है। उन्होंने कहा कि बजरंगबली का अपमान करके PFI को किस तरह बचाया जाए, इसकी ही चेष्टा कांग्रेस पार्टी करती है। तुष्टिकरण की राजनीति की ये पराकाष्ठा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं जिन्हें लगता है कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही महिलाओं पर हमला करते हैं और महिलाओं के खिलाफ हैं? आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कर्नाटक के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है।

इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य देखिए, मैं आज जब यहां हनुमान जी को नमन करने आया हूं उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन्ना भी ज़िंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र जारी नहीं करते। अपने बयान में सरमा ने कहा कि गृह मंत्री ने PFI को बैन किया तो कांग्रेस बोल रही है कि वे बजरंग दल को बैन करेंगे, मुस्लिम आरक्षण को फिर से शुरु करेंगे।

भाजपा-कांग्रेस के घोषणा पत्र में अंतर

भाजपा– गरीबों को साल में तीन बार गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि ये सिलेंडर उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली में दिया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का वादा भी किया है। इसके जरिए गरीबों को सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एलान किया है कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करती है तो बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन पोषण स्कीम के तहत आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा। नंदिनी दूध को लेकर पहले से ही सूबे में खूब सियासत चल रही है। 10 लाख गरीबों को घर, दलित महिलाओं के नाम 10 हजार की एफडी, हर महीने गरीबों को पांच किलो राशन, सूबे में समान नागरिक संहिता लागू करने का भी वादा किया है। भाजपा के बड़े वादों में पांच लाख तक के लोन पर किसी तरह का ब्याज न लेना, किसानों को बीज के लिए 10 हजार रुपये देना और वरिष्ठ नागरिकों का साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना भी शामिल है।

कांग्रेस – सरकार बनने पर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करके राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने, 63 सीमावर्ती तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति का विकास, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने जैसे वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने प्रत्येक परिवार के महिला मुखिया को हर महीने दो हजार रुपये, बेरोजगार स्नातकों को दो साल तक प्रतिमाह दो हजार रुपये, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को डेढ़ हजार रुपये, रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रतिमाह पांच हजार रुपये विशेष भत्ता देने का भी वादा किया है। हालांकि, घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा चर्चा सूबे में नफरत फैलाने वाले संगठनों को बैन लगाने के वादे की हो रही है।

इन दिनों ✍ शशांक शर्मा

आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

प्रदेश में आरक्षण को लेकर भ्रम का वातावरण है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर मीडिया से राजनीति तक जिस प्रकार से प्रचारित किया गया, उससे भ्रम और बढ़ गया है। सोमवार को इस तरह की खबर आई कि प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को जारी रखने का फैसला दे दिया है। मतलब उच्च न्यायालय ने सितंबर में प्रदेश में लागू 58% आरक्षण को खारिज कर दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस खबर के बाद सरकार ने भी बैठक कर भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया ऐसी खबर आई। आज जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिली तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने 58% को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने केवल प्रदेश में भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है। इस आदेश में न तो उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख है और न ही आरक्षण कोटा को लेकर कोई आंकड़ा। ऑर्डर में तो यह भी लिखा है कि प्रदेश में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह कोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा। अब सवाल यह भाई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 58% के बारे में कुछ कहा ही नहीं तो मीडिया से लेकर सरकार तक में इसकी चर्चा कैसे हुई? इसका दोषी कौन है? पहली बात तो सरकार के पक्ष रखने वाले वकीलों ने मीडिया और सरकार को जो बताया होगा वही बात सार्वजनिक हुई होगी, इसका मतलब इस भ्रम को फैलाने के दोषी वकील हैं? या मीडिया ने बिना जानकारी लिए आधे अधूरे तथ्य के आधार पर समाचार परोस दिया? अगर ऐसा है भी तो सरकार को तो आदेश की कॉपी मिलने तक इंतजार कर लेना था, इसका श्रेय लेने की हड़बड़ी में शासन ने भी लापरवाही की। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संकट और गहरा गया है। हालांकि सरकार की जिद है कि 76% पर ही भार्ती करनी है वरना देश भर में 50% आरक्षण कोटा के आधार पर भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर सकती है और नई परीक्षाएं भी ले सकती है। जब निर्णय आएगा तब नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। सरकार को विषय की गंभीरता समझनी चाहिए, छात्र परेशान हैं, महाविद्यालयों में प्रवेश बाधित होंगी। पीढ़ी का नुकसान है, ऐसे में सरकार को युवाओं को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चुनाव करीब है और वोटबैंक का सवाल है इसलिए कुछ निर्णय होगा इसकी संभावना कम है। वैसे भी आरक्षण को लेकर पिछले 6-8 महीनों से केवल राजनीति हो रही, जिसका खामियाजा पढ़ने वाले बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में आरक्षण का मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले से पेचीदा हुआ जब प्रदेश में 2012 से लागू 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया गया। इसके बाद प्रदेश में वापस 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई। इस निर्णय से सबसे अधिक नुकसान जनजातीय समाज को हुआ क्योंकि 2012 में जनजातीय वर्ग के आरक्षण का कोटा 20% से बढ़ाकर 32% किया गया था वहीं अनुसूचित जाति की आबादी के अनुसार आरक्षण को 16% से घटाकर 12% किया गया था। इस निर्णय से नाराज अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधि उच्च न्यायालय गए थे।

पूर्व गृहमंत्री का गंभीर आरोप, नक्सल हमले में कांग्रेस का हाथ

कहा- झीरम हमले में कुछ लोग कैसे बचे

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने प्रदेश में नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले और वर्तमान में हुए नक्सली हमले के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ है। इसके लिए ननकी राम ने झीरम घाटी हत्याकांड का उदाहरण भी दिया। कहा कि, उनके गृहमंत्री रहने के दौरान इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उसमें कांग्रेस का एक नेता बाइक पर भाग निकला। आखिर वहां पर बाइक कहां से मिली। पूर्व गृहमंत्री मंगलवार को मीडिया से बात कर रहे थे।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व गृहमंत्री कवंर ने कहा कि, कांग्रेस में आपस में जो फूट थी, कहीं न कहीं उसी के कारण झीरम में हमला हुआ। अगर नक्सली हमला अचानक हुआ तो कुछ लोग वहां से बचकर कैसे निकल जाते। उन्होंने कहा कि, तब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमने केंद्रीय फोर्स मांगी। इसके लिए केंद्र को चिठ्ठी लिखी थी, पर फोर्स नहीं दी गई। आज बस्तर में फोर्स तो है, लेकिन सरकार उसका सद्पयोग नहीं कर पा रही है। कंवर पहले भी गुटबाजी को लेकर हमले की बात कह चुके हैं।

साय का पार्टी बदलना गलत

भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय के पार्टी छोड़ने को लेकर भी ननकी राम कंवर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, आज देश में कांग्रेस की स्थिति देखते हुए उनका पार्टी बदलना गलत है। आज तो कांग्रेस का नामोनिशान मिट रहा है। ऐसे समय मे कांग्रेस में जाना कहां तक सही है। भाजपा ने उन्हें जो दिया, वो किसी जूनियर नेता को नहीं मिला। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि, किसी व्यक्ति के जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता।

झीरम घाटी नक्सल हमले में 32 लोगों की गई थी जान

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 25 मई 2013 की शाम को दरभा की झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला किया था। उस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने चारों ओर से घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके चलते लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। इस हमले में 32 लोगों की जान गई। इसमें बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेसी नेता महेन्द्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल के नाम भी शामिल हैं। इस हमले को कांग्रेस ने सुपारी किलिंग करार दिया था।

प्रमुख समाचार

गुजरात हाईकोर्ट से राहुल को नहीं मिली अंतरिम राहत

गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2019 के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। निचली अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को उनकी 2019 की टिप्पणी %कैसे सभी चोरों का मोदी सरनेम एक जैसा है% के लिए दोषी ठहराया। राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसने उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राहुल गांधी को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह छुट्टी के बाद अपना फैसला जून में सुनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का द केरल स्टोरी पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि यह नफरत फैलाने वाली ऑडियो-विजुअल प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट के जज के एम जोसेफ और बी वी नागरत्ना की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा ने बताया कि शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म के ट्रेलर को 1.6 करोड़ बार देखा जा चुका है। पाशा ने दावा किया, यह फिल्म सबसे खराब किस्म की अभद्र है और पूरी तरह से ऑडियो-विजुअल प्रोपेंडा है। बेंच ने कहा, इस फिल्म को प्रमाणन मिला है और बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पोडियम पर आ जाता है और अनियंत्रित भाषण देना शुरू कर देता है। यदि आप फिल्म की रिलीज को चुनौती देना चाहते हैं, आपको उचित मंच के माध्यम से प्रमाणन को चुनौती देनी चाहिए।

शरद को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने में दो से तीन दिन लगेंगे, एनसीपी कार्यकर्ताओं से बोले अजित

नई दिल्ली। देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने राकांपा प्रमुख पद से इस्तीफे का ऐलान कर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके इस ऐलान के बाद उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई। पार्टी कार्यकर्ता शरद पवार के अपने फैसले को वापस लेने की बात कहने लगे। इतना ही, कुछ कार्यकर्ता तो धरने पर भी बैठ गए। उन कार्यकर्ताओं को अजीत पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने समझाने की कोशिश की। राकांपा नेता अजित पवार ने विरोध कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कहा कि शरद पवार को अपने फैसले (राकांपा प्रमुख के रूप में पद छोड़ने) पर पुनर्विचार करने में दो से तीन दिन लगेंगे। अजित पवार ने कहा कि हमने उनसे (शरद पवार) कहा कि कार्यकर्ता काफी परेशान हैं। हमने उनसे यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के साथ-साथ वे पार्टी अध्यक्ष भी बने रहें।

भाजपा नेता का अपहरण कर हत्या, भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक नेता के साथ पत्नी के सामने मारपीट करने के बाद अपहरण और फिर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। भाजपा ने हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगाया है। घटना पूर्व मेदिनीपुर जिले की है। मृतक की पहचान विजय कृष्ण भुइयां के रूप में हुई है। वे बूथ अध्यक्ष थे। भाजपा ने सोमवार रात से ही विरोध-प्रदर्शन कर थाने का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम को घर लौट रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी के सामने उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद बाइक सवार तृणमूल के कई नेता आए और उसे घर से उठा कर ले गए। उसके बाद उसकी हत्या कर घर से थोड़ी दूरी पर शव फेंक दिया गया। रात को ही मयना के भाजपा विधायक अशोक डिंडा के नेतृत्व में थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, नए सिरे से सुनवाई के आदेश

इलाहाबाद। उच्च न्यायालय ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह ट्रस्ट, मथुरा द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं का निस्तारण किया, जिसमें मथुरा के जिला न्यायाधीश के 19 मई, 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी। ईदगाह ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड ने जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। लीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सिविल सूट संख्या को स्थगित करने के निर्देश के साथ मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। मुकदमा दायर किए जाने के समय दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) ने इस वाद को दीवानी मुकदमा के तौर पर दर्ज नहीं किया बल्कि इसे विविध मामले के तौर पर दर्ज किया जिसका आधार यह था कि वादी संख्या 3 से 8 मथुरा के निवासी नहीं हैं, जबकि प्रश्नगत संपत्ति जिला मथुरा में स्थित है।

लड़की के प्यार में पुणे के छात्र विशाल की जिंदगी हुई बर्बाद!

झारखंड के एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला विशाल 2004 में पढ़ाई के लिए पुणे आया था। गिरफ्तारी के समय वह हडपसर कॉलेज में पढ़ रहा था। 2005 में विशाल याहू मैसेंजर के जरिए एक लड़की के संपर्क में आया। उसने खुद को पाकिस्तान के कराची की रहने वाली फातिमा सल्लुद्दीन शा के रूप में प्रजेंट किया। पुलिस ने कहा कि वह फातिमा के साथ चैट करने के लिए एक इंटरनेट कैफे जाता था और दोनों रोजाना घंटों चैट करते थे। दोनों ने अपने परिवारों का विवरण साझा किया और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फातिमा ने कहा कि सलाहुद्दीन एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सेना अधिकारी थे। विशाल को प्यार हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए फातिमा कथित तौर पर राजी हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने उसके साथ एक पाकिस्तानी सेल फोन नंबर साझा किया। एसटीडी बूथ के मालिक ने पुलिस को बताया कि विशाल ने उसे स्थानीय एसटीडी बूथ से इस नंबर पर कॉल किया, जिसमें 1.5 लाख रुपये का बिल आया। पुलिस ने कहा कि उसने केवल 40,000 रुपये का भुगतान किया।

विशाल ने पाकिस्तान में फातिमा के माता-पिता से भी फोन पर बात की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, हालांकि उन्होंने शुरुआत में उसके शादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में वे इस शर्त पर तैयार हो गए कि वह इस्लाम कबूल कर लेगा। फातिमा और उसके पिता ने कथित तौर पर विशाल को पाकिस्तान आमंत्रित किया। उसके पिता ने उसे यह कहकर फुसलाया कि वह अपनी शादी के बाद लंदन में बस सकता है और वहां व्यवसाय

कर सकता है। विशाल ने पाकिस्तान के वीजा के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार, यह तब है जब सलाहुद्दीन ने उन्हें नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी सैयद एस हुसैन तिर्मिज़ी का संपर्क नंबर दिया था। तिर्मिज़ी और पाकिस्तान उच्चायोग के एक अन्य कर्मचारी जावेद उर्फ अब्दुल लतीफ़ को भी इस मामले में आरोपी और साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया।

विशाल ने कथित तौर पर तिर्मिज़ी से संपर्क किया और उसके दस्तावेज़ सौंपे। इस दौरान वह दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक लॉज में रुका और उसने फातिमा और उसके पिता से पैसे लिए। पुणे पुलिस ने अगस्त और दिसंबर 2006 के बीच नौ ऐसे पैसों के लेन-देन का विवरण अदालत के सामने पेश किया। पुलिस ने कहा कि तिर्मिज़ी और लतीफ़ ने विशाल के पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा की व्यवस्था की थी। जांच से पता चला कि विशाल ने दो बार 14 अक्टूबर, 2006 को चार दिनों के लिए और फिर 23 जनवरी, 2007 को दो सप्ताह से अधिक समय के लिए पाकिस्तान का दौरा किया।

इस मामले के जांच अधिकारी भानुप्रताप बर्गे ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि विशाल पाकिस्तान से लौटा है और उसके पास पुणे और उसके आसपास के सैन्य प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की तस्वीरों वाले कुछ गुप्त दस्तावेज और सीडी हैं। हमारे पास जानकारी थी कि वह पाकिस्तान में किसी को महत्वपूर्ण जानकारी सौंपने की योजना बना रहा था, इसलिए हमने निगरानी शुरू कर दी। विशाल को 8 अप्रैल, 2007 को पुणे शहर पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान, पुलिस ने कथित तौर पर पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप (बीईजी), दक्षिणी कमान आदि जैसे विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों की इमारतों की तस्वीरों वाली सीडी बरामद की।

विशाल ने पुलिस को दिए अपने बयानों में फातिमा और उसके परिवार से मिलने, कराची में उनके आवास पर रहने के बारे में जानकारी दी। जांच में यह भी पता चला कि विशाल ने इस्लाम कबूल करने के लिए पुणे और मालेगांव में कुछ मुस्लिम मौलवियों से संपर्क किया था।

पुलिस ने कहा कि सलाहुद्दीन ने कथित तौर पर मौलवी को बताया कि विशाल पहले ही इस्लाम कबूल कर चुका है और उसे %बिलाल% नाम दिया गया है। पुलिस ने अदालत के समक्ष %बिलाल% के संदर्भ में एक ईमेल रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। 29 मार्च, 2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुचित्रा घोडके की अदालत ने विशाल को आईपीसी की धारा 120 बी और ओएसए की धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे सात साल कैद की सजा सुनाई।

मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी डिप्टी कमांडर ढेर, कुछ नक्सली घायल

गरियाबंद। मंगलवार को अपने नियमित सर्चिंग अभियान पर निकले पुलिस दस्ते का नक्सलियों के साथ आमना-सामना हो गया जिसमें एक 5 लाख का इनामी डिप्टी कमांडर नक्सली मारा गया तथा कुछ नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिली है। इस मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाके में सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को जिला गरियाबंद के थाना जुगाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करलाझर एवं नागेश के समीप पहाड़ी क्षेत्र में इंदागांव एरिया कमेटी के 12-15 सशस्त्र नक्सलियों के मौजूदगी खबर मिली। जिस पर जिला गरियाबंद से कोबरा बटालियन 207, ई-30 एवं सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन की विशेष कार्ययोजना तैयार कर सर्चिंग के लिए रवाना हुई। इसी दौरान थाना जुगाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करलाझर में मंगलवार करीब सुबह 9:20 बजे नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने तत्काल मोर्चा सम्हाला और जवाबी फायरिंग किया।

जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, इसके बाद जवानों ने सर्चिंग अभियान शुरु किया जिसमें एक नक्सली का शव बरामद किया गया जिसकी पहचान उदंती

एलओएस का डिप्टी कमांडर नंदलाल के रुप में की गई जिस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सली के पास से 3 नाट 3 की बंदूकें भी जब्त की गई है। वहीं कई उपयोगी सामान भी जब्त किए गए हैं। जवानों ने आशंका जताई है कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हुए है जिन्हें वे अपने साथ ले गए है ऐसी संभावना है।

इसके पहले इसी क्षेत्र से ओडिशा पुलिस ने 2 मिलीशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो कि शोभा क्षेत्र के रहने हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को लगातार नक्सल मूवेमेंट का इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद आज पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया।

नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर ग्रामीण की हत्या कर दी

बीजापुर। मिरतुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तर्रेम के तुर्रेपारा निवासी दिव्यांग ग्रामीण अवलम हड़मा को नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में अपहरण के बाद धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दिया है। वारदात के बाद शव को थाने के नजदीक लाकर फेंक दिया, जिसका शव मंगलवार को बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ग्रामीण अवलम हड़मा जिले के तर्रेम के तुर्रेपारा का रहने वाला था, जिसकी एक आंख खराब थी। सोमवार की शाम गांव के अन्य ग्रामीणों के साथ जंगल गया हुआ था। जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान ग्रामीण वेशभूषा में कुछ नक्सली मौके पर पहुंचकर उसका अपहरण कर अपने साथ जंगल की तरफ लेकर चले गए। वहां मौजूद अन्य ग्रामीणों को वापस गांव जाने कहा गया। इसके बाद ग्रामीण अवलम हड़मा की हत्या कर थाने के नजदीक शव को फेंक दिया।

नक्सल पीड़ित परिवार का हुक्का-पानी बंद, लेन-देन पर 2000 जुर्माना

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सल प्रभावित गांव में दबंगों ने एक विधवा के परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया है। उससे किसी भी तरह का लेनदेन करने या फिर बात करने पर दो हजार रुपये जुर्माने का फरमान जारी किया है। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि अचानक सड़क पर तबीयत खराब होने पर पहले से बहिष्कृत एक युवक ने उसे बाइक से घर तक छोड़ा था। फिलहाल महिला अपनी दो बेटियों के साथ घर में कैद है। दबंगों ने उसे गांव छोड़कर जाने को कहा है। परिवार ने इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की है।

नक्सलियों ने कर दी थी पति की हत्या

दरअसल, सारा मामला नक्सल प्रभावित पंचायत विकासपल्ली के पीवी 105 गांव का है। यहां रहने वाली सुषमा हालदार के पति की करीब 10 साल पहले नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नक्सलियों को उस पर पुलिस मुखबिरी का शक था। इसके बाद महिला अपनी दो बेटियों को लेकर जगदलपुर चली गई। गांव में हालात ठीक हुए थे, वह फिर लौटी है। उसकी एक बेटी 19 और दूसरी 15 साल की है। दोनों बेटियां पढ़ती हैं। जबकि महिला सुषमा गांव के ही स्कूल में रसोइया का काम करती है।

बहिष्कृत युवक ने घर छोड़ा तो उसे पीटा गया

महिला ने कलेक्टर को सौंपी शिकायत में कहा है कि, गांव के कुछ गुंडे किस्म के लोग उसे आए दिन परेशान करते हैं। गांव के एक युवक का पूर्व में बहिष्कार किया जा चुका है। सुषमा ने बताया कि एक दिन जब वह साप्ताहिक बाजार से घर लौट रही थी, तो रास्ते में चक्कर आ गया। इस पर उसी युवक ने बाइक से घर तक पहुंचाया। इससे नाराज होकर गांव के गुंडों ने युवक से मारपीट की। फिर 29 अप्रैल की रात गांव में मीटिंग की गई और उसके परिवार का भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। इसकी जानकारी पड़ोसी ने दी।

बेटियों को भी स्कूल भेजने पर दी धमकी

पड़ोसी की ओर से महिला को बताया गया कि गांव में किसी से भी लेनदेन करने पर रोक लगा दी है। उसे पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। न कोई महिला के घर आएगा और न वह किसी के घर जा सकेगी। सरकारी राशन नहीं मिलेगा, दुकान से भी खरीदी नहीं कर सकेगी। किसी के भी बात करने पर दो हजार जुर्माना लगेगा। उसे रसोइया का काम भी छोड़ना पड़ेगा। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि, उसने मुखिया के घर जाकर बात की, गांव छोड़ने की धमकी दी। साथ ही कहा कि बेटी स्कूल गई तो कुछ भी हो सकता है।

नवीन एटीएम का शुभारंभ, किसानों को प्राप्त होगा बेहतर सुविधा

कोंडागांव। किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह विधायक कोंडागांव मोहन मरकाम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर जिला कोंडागांव की नवीन एटीएम शाखा अनंतपुर का विधि विधान के साथ लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पे उपस्थित क्षेत्रवासियों किसान बंधुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, छग की कांग्रेस नेता भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं से किए वादे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही हैं। सरकार बनते ही मात्र 2 घंटे के अंदर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया पहले जहां धान का समर्थन मूल्य 1 हजार 600 व 1 हजार 700 रुपए मिलता था, उसे अपने वादे अनुसार 2 हजार 500 में खरीदना प्रारम्भ किया और इस वर्ष किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2 हजार 640 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा हैं और आने वाले समय मे प्रदेश के अन्नदाताओं को जो कड़ी धूप, ठंड, बारिश में भी अपनी मेहनत से अन्न उगाते हैं और देशवासियों का पेट भरते हैं उन्हें 2 हजार 800 रुपए तक धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। आज पूरे देश मे धान को सबसे अधिक समर्थन मूल्य में खरीदने वाली कोई सरकार हैं तो वो छग की भूपेश बघेल के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार हैं स्वाभाविक हैं जब किसान के खाते में पैसा होगा तो बैंक में भीड़ होगी और इसी परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए आज ग्राम अंनतपुर में जिला सहकारी बैंक एटीएम का शुभारंभ हो रहा हैं। जिससे हमारे अन्नदाता हमारे किसान भाइयों को अपने खाते से रकम निकालने में आसानी हो और उनका समय भी व्यर्थ न हो।

लोकार्पण के अवसर पर जिलाध्यक्ष झुमुक लाल दीवान, जिला पंचायत सदस्य हेमलाल बघेल, जनपद सदस्य भिंगुराम कश्यप, रमेश मरकाम, लखु पोयाम, शिल्प बोर्ड सदस्य शंकर विश्वकर्मा, सांसद प्रतिनिधि चंद्र बघेल, रदमा बघेल सरपंच, सुखलाल बघेल, हरेंद्र पांडे, देवाराम वट्टी, मंगलू राम पोयम, बुधराम सागर, शंकर नाग, भगरु नाग, मोतीलाल नाग, रघु नाग क्षेत्र के किसान बन्धु और विभागीय अधिकारी कर्मचारी गण प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

मजदूर दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली

कोरबा। कोरबा जिले में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भारत एलुमिनियम एम्प्लाइज यूनियन, सीटू बालको के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुवात रैली से हुई। रैली सीटू कार्यालय से मिनीमाता चौक तक निकाली गई। तत्पश्चात बालको सीटू के अध्यक्ष कॉमरेड एस.घोष के द्वारा ध्वजारोहण कर व शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बालको सीटू के द्वारा मजदूर दिवस पर विभिन्न क्षेत्र के मजदूरों को पुरस्कृत कर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीटू के प्रदेशाध्यक्ष कॉमरेड एस एन बैनर्जी, छग परिवहन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कॉमरेड जी डी महंत, ताहिर खान, एनटीपीसी कामगार यूनियन के महासचिव कॉमरेड गुरुमूर्ति, कॉमरेड कश्यप, बालको सीटू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉमरेड आर.डी चन्द्रा शामिल हुए।

कॉमरेड एस एन बैनर्जी ने कार्यक्रम की शुरूवात में मई दिवस के घोषणा पत्र को पढ़ कर किया व उन्होंने मजदूरों को आने वाले समय के लिए एकजुट हो कर संघर्ष करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन बालको सीटू के महासचिव कॉमरेड अमित गुप्ता के द्वारा किया गया। कॉमरेड संजय अग्रवाल, धर्नजय चन्द्रा, राजेश नागराज, सन्त राम महंत, नितेश साहू, ललित यादव, अजय शर्मा, धीरज भोंसले, एस के यादव, डिकेश्वर देवांगन, रामपूजन, रविदास, रामलाल, विजय सेन व टीम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत मे कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन कॉमरेड आर डी चन्द्रा ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों के संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया।

328 करोड़ की लागत से 74 हजार घरों में नल लगे, फिर भी साल भर से 222 गांव प्यासे

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (लक्कड़) जिले में केंद्र सरकार की हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 327 करोड़ 91 लाख की लागत से 222 गांवों के 74 हजार 838 घरों ने नल लगाए, पर साल भर बीतने के बाद भी इनमें पानी नहीं आया। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर गांव आदिवासियों के हैं। कलेक्टर ऋचि महोबिया भी इसमें अनियमितता की बात स्वीकार करती हैं। हालांकि वह इसे दुरुस्त कराने की बात कहती हैं।

ठोड़ी का गंदा पानी पी रहे लोग

गौरेला की आदिवासी ग्राम पंचायत टीडी में साल भर पहले ही लोगों के घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया था। हालांकि इन नलों से पानी अभी तक नहीं आया। इसके चलते यहां के ग्रामीण आज भी पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे ठोड़ी से गंदा पानी लेकर आते हैं और उसे पीने के लिए मजबूर हैं। यही स्थिति पुटा ग्राम पंचायत के टीडी गांव में भी है। गांव की संतरा बाई बताती हैं कि, नल कलेक्शन तो लगा है, पर पानी डेढ़ सालों में आज तक नहीं मिला। ऐसे ही हालात करंगरा सहित अन्य गांवों में भी हैं।

नलों में पानी आया नहीं, हैंडपंप में भी मोटर लगा दी

विशेष जनजाति बैगा बाहुल्य करंगरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नलों से आज तक पानी नहीं आया है। आता भी है तो बस उस नल से जो टंकी के ही नीचे लगाया गया है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में जिस हैंडपंप से लोगों को पहले पानी मिलता था, उसमें भी ठेकेदार ने मोटर फिट करवा दी। दूरस्थ इलाका होने के कारण कई बार घंटों बिजली नहीं रहती। लाल जी बैगा बतला रहे हैं कि हैंडपंप से पानी ले आते थे, उसमें भी मशीन डाल दी। अब बिजली बंद तो पानी नहीं मिलता। इसके चलते दूर से पानी लाना पड़ता है।

पेयजल लाइन जमीन के नीचे की जगह ऊपर ही बिछाई गई

योजना के तहत ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। ठेकेदारों ने पेयजल लाइन को जमीन के तीन फीट नीचे डालने की जगह, ऊपर से ही बिछा दिया। इसके कारण जगह-जगह से पेयजल लाइन फूट गई है। इसके कारण भी पानी नहीं आता। कई गांवों में पानी की टंकी को ही नीचे लगा दिया गया है। करंगरा गांव में रहने वाले अमर साए बैगा बताते हैं कि, नल काफी ऊपर है, इसके कारण भी पानी नहीं आता है। हालांकि इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जांच तक नहीं की।

गुणवत्ताहीन टंकी बनाई, फिर तोड़ने के आदेश, अब अधूरी छोड़ी

जिला मुख्यालय से करीब 15 किमी दूर मरवाही ब्लॉक का महोरा गांव। यहां पेय जल की समस्या सालों से है। ठेकेदारों ने पानी की टंकी बनाई और हर घर में नल लगाया। काम विभाग के इंजीनियर, एसडीओ और ईई की निगरानी में हुआ। नतीजा स्कूल परिसर में बनाई गई इस टंकी को गुणवत्ताहीन बताते हुए तोड़ने का आदेश अफसरों ने कर दिया। उसमें भी लापरवाही बरती गई। ऊपरी हिस्सा तोड़कर उसे छोड़ दिया गया। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि टंकी के इस्तेमाल के बाद हादसा हो सकता था, अब भी ऐसी ही स्थिति है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विधायक जैन ने आकाश को भेंट किया स्मृति चिन्ह

जगदलपुर। सोमवार शाम संसदीय सचिव व ज ग द ल पु र विधायक रेखचंद जैन ने यूपीएससी के माध्यम से रक्षा सेवा के लिए चुने गए शहर के युवा आकाश राव से उनके घर जाकर भेंट की। उन्हें बुके भेंटकर स्मृति चिन्ह दिया और मिठाई से उनका, माता - पिता अप्पा राव व अन्य परिजनों का मुंह मीठा करवाया। विधायक श्री जैन ने श्री आकाश राव के चयन को शहर तथा राज्य के लिए गौरव एवं प्रमुख उपलब्धि बताया। उन्होने आकाश से चयन तथा परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी लेते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही, कहा कि वे उन्हें भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होते देखना चाहते हैं। इस मौके पर पर केशव राव, दिगम्बर राव, पी रामकृष्णा नायडू, राजू राव, ईश्वर सेट्टी, श्री साई, महेश ठाकुर, गौरनाथ नाग, एमआइसी सदस्य राजेश राय, पार्षद सूर्या पाणि, संतोष सिंह, विजय सिंह आदि मौजूद थे।

बीएसएफ का अफसर बनकर देता नौकरी का झांसा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पुलिस ने दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बिहार निवासी प्रकाश कुमार की गिरफ्तारी गुरुगांव के मानेसर से की गई है। जबकि दूसरे आरोपी अमन गौतम को पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के इंदरपुरी से पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चार मोबाइल, अलग-अलग बैंकों के पासबुक और आधार कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी प्रकाश कुमार खुद को बीएसएफ का अफसर बताता था। फिर सेना में नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करता। वहीं आरोपी अमन गौतम क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने या बंद करने के नाम पर फ्रॉड करता। जानकारी के मुताबिक, छोटेदेवड़ा निवासी कमललोचन बघेल ने बस्तर थाने में मामला दर्ज कराया था कि, उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बीएसएफ का अफसर बताया। फिर बीएसएफ में नौकरी लगवाने की बात कही। आरोपी ने विश्वास दिलाने के लिए अपना आईडी कार्ड भी व्हॉट्सएप पर भेजा। बातों में आकर कमल लोचन ने किस्तों में 1.80 लाख रुपये उसके एसबीआई खाते में ट्रांसफर कर दिए।

नेवई गौठान मे कांग्रेसियों ने मजदूरों का सम्मान किया

रिसाली। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण नगर पालिका निगम रिसाली द्वारा नेवई के गौठान मे सोमवार को मजदूर दिवस मनाया गया।कांग्रेस नेताओ ने मजदूरों के साथ बोरे बासी खाकर उनका शॉल श्रीफ्ल से सम्मान किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेन्द्र साहू भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकुंद कुमार भाऊ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चंद्रकांत कांरे महापौर नगर पालिका निगम रिसाली श्रीमती शशि अशोक सिन्हा सभापति केशव बंछोर, ब्लॉक क्र. 6 के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की प्रभारी श्रीमती सरिता जितेंद्र साहू अनुपमा गोस्वामी महापौर परिषद के सदस्य अनुप डे चंद्रभान सिंह ठाकुर चंद्र प्रकाश निगम सिंग गोविन्द चतुर्वेदी सोनिया देवांगन ईशवरी साहू परमेश्वर दास पार्षद विनय नेताम डोमन बारले श्रीमती शिला नारखेड़े श्रीमती सरिता देवांगन श्रीमती जमुना ठाकुर एलडरमेन तरुण बंजारे मो. निजाम संतु दास मानिक पुरी अजीत यादव आदि उपस्थित थे।

साहू समाज के प्रदेश पदाधिकारी बिरनपुर पहुँचे

पाटन। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव मे साहू समाज के प्रदेश पदाधिकारी स्व भूनेश्वर साहू के घर पहुचे। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू, दुर्ग जिला कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष अश्वनी साहू उनके परिवार जनो से मुलाकात की शोकाकुल परिवार से मिलकर हाल-चाल जाना व स्वर्गीय भुनेश्वर साहू के पिताजी व उनके भाई से मिलकर शोकाकुल परिवार का हालचाल जाना। साथ ही परिवार को हर संभव मदद करने की बात जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू व दुर्ग कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष अश्वनी साहू ने कही। इस मौके पर परिवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने 51000 रूपये व दुर्ग कृषि उपज मंडी अध्यक्ष अश्वनी साहू ने 21000 रूपये शोकाकुल परिवार को प्रदान की साथ ही हर संभव मदद करने की बात कही. वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने स्वर्गीय भुनेश्वर साहू के परिवार को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आप के परिवार से जो वादा किया है।

कोरबा में जानलेवा मकड़ी के डंक से बेहोश हुई महिला

कोरबा। घरों की छत और दीवारों पर अक्सर हम जाले लगे देखते हैं। कई में छोटी-छोटी या बड़ी मकड़ियां होती हैं। कई बार हम जालों को साफ कर देते हैं। कई बार इन मकड़ियों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकती हैं। कोरबा में ऐसा ही मामला सामने आया है। जब एक मकड़ी के काटने से महिला की जान पर बन आई। हालत बिगड़ने पर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने महिला को काटने वाली मकड़ी का नाम टारेंट्युला बताया है। कहा कि, इसके काटने से जान भी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक, पाली निवासी हेमा यादव पत्नी रविकांत यादव मंगलवार सुबह घर में बर्तन साफ कर रही थी। इसी दौरान उसके पैर में मकड़ी ने काट लिया। थोड़ी देर बाद बर्तन धोकर महिला कमरे में चली गई, लेकिन उसके पैर में काफी तेज दर्द होने लगा। पति रविकांत वहां पहुंचा तो देखा कि वह मकड़ी सामान्य से काफी बड़ी थी। फिर कमरे में पहुंचा तो देखा कि हेमा बेहोश हो चुकी थी। इस पर उसे तत्काल ही जिला अस्पताल ले गए।

जनता के बीच कांग्रेस की आवाज मुखर करेंगे वक्ता : गोस्वामी

कोंडागांव। कोंडागांव जिले में कांग्रेस भवन कोंडागांव में वक्ता चयन के प्रभारी सुनील गोस्वामी ने कांग्रेस के वक्ता बनने इच्छुक प्रतिभागियों से उनकी वाकपटुता व अपनी बातों के प्रस्तुतीकरण सहित अन्य बारीकियों से रूबरू हुए। वक्ता चयन प्रभारी कोंडागांव सुनील गोस्वामी ने वक्ता चयन के उद्देश्य से उपस्थित कांग्रेस जनों को अवगत कराते हुए कहा कि सभी प्रतिभागी अपनी अभिव्यक्ति और पार्टी द्वारा निर्धारित विषय सूची और स्थानीय विषयो के अनुसार अपनी बातों को रखे।

उन्होंने कहा कि वक्ता कांग्रेस के मुख्यपात्र होते हैं और उन्हें विषयों की जानकारी के साथ-साथ अपनी पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर चलते हुए संगठन की जिम्मेदारी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता के बीच ले जाकर जहां हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाना होता हैं वही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए विरोधियों के झूठ फरेब अफवाह का मुंहतोड़

जवाब भी देने का कार्य कांग्रेस पार्टी की ओर से वक्ता को करना होता हैं। पार्टी के आयोजित सभा, कार्यक्रम में पार्टी की ओर से अपनी बात भी रखने प्रदेश कांग्रेस कमेटी योग्य वक्ताओं के चयन के लिए यह अभियान प्रारंभ किया हैं। कोंडागांव जिला में वक्ताओं की कोई कमी नहीं है यहां के वक्ता समृद्ध सशक्त और मंझे हुए हैं बस जरूरत हैं उन्हें सामने लाने की उन्हें तराशकर उनकी आवाज को मुखर करने की वक्ताओं के नामों को पीसीसी में प्रस्तुत करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के द्वारा अधिकृत वक्ताओं की सूची जारी की जाएगी और उन्हें प्रशिक्षित कर मैदान में उतारा जाएगा वक्ता चयन अभियान के उद्देश्य से अवगत कराने के पश्चात पार्टी के आंतरिक साक्षात्कार के रूप में चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं।

इस वक्ता चयन अभियान कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष झुमुकलाल दीवान, विधायक प्रतिनिधि बुधराम नेताम, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव जेपी यादव जिला उपाध्यक्ष बिरस साहू, जिला महामंत्री गोतेश गांधी, ब्लाक अध्यक्षगण तरुण गोलछा, भरत देवांगन, शंकर मंडावी, कांकेर ब्लाक अध्यक्ष मनोज जैन, प्रदेश डेलीगेट रामकुमार कश्यप, राजेंद्र साहू,जनपद उपाध्यक्ष मनोज सेठिया, शकूर खान, जिला प्रवक्ता शिल्पा देवांगन, नन्दू दीवान, वरुण सेठिया, लोकमन दीवान, हेमलाल बघेल, श्याम सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष वर्षा यादव, पार्षद इरशाद खान, गजेंद्र राठौर, ब्रिज सोढ़ी, बंशी यादव, भिंगु राम कश्यप, वीनोद सोरी, चन्दर बघेल, ब्रम्हा मरकाम, अनिता पोयाम, सुकमु कोर्राम, प्रवीण मिश्रा, गीतेश बघेल सहित भारी संख्या में प्रतिभागी और पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

न्यायाधिकरण की टीम ने बांगो व दर्री बांध का किया निरीक्षण

कोरबा। महानदी के जल को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में काफी समय से विवाद चल रहा है। सेंट्रल वाटर विवाद की न्यायाधिकरण टीम इस मामले के निराकरण में जुटी हुई है। 40 सदस्यों वाली टीम ने सोमवार को बंगो व हसदेव दर्री बांध का निरीक्षण किया। टीम में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के अलावा कई अधिकारी शामिल रहे। मूल रूप से कोरबा जिले के बांध और बैराज सहित कई संसाधनों का आकलन इस टीम ने किया।

विभिन्न राज्यों में काफी समय से बने हुए जल विभाग के मामलों को निपटाने के लिए केंद्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण बीते वर्षों में अपना काम करता रहा है। महा नदी जल विवाद का स्थाई समाधान खोजने के लिए सरकार ने इसे जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा की तरफ जाने वाले

महानदी के पानी को लेकर काफी समय से विवाद के कारण बने हुए हैं और इसकी अधिकारिता पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सरकार ने पिछले चार दशक से बढ़ते विवाद और शिकायतों के बीच 40 सदस्यों की टीम को प्रारंभिक चरण में कोरबा जिले के दौरे पर भेजा गया है। कहा जा रहा है कि ओडिशा सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बीते वर्षों में याचिका दायर की गई है और पानी के निर्दिष्ट उपयोग को लेकर अपना पक्ष रखा गया है। जबकि छत्तीसगढ़ अपनी तरह से महानदी और इसके जल संसाधन पर स्वाभाविक रूप से अधिकार जताता रहा है। इसके पीछे उसके अपने तर्क है। पूरे मामले को समझने और इसके अध्ययन के बांध ट्रिब्यूनल की टीम ने प्रदेश में 18 अप्रैल से दौरा शुरू किया है इसके अगले चरण में 30 अप्रैल से बिलासपुर संभाग के दौरे पर टीम सक्रिय हुई है। इसके अंतर्गत कोरबा जिले में हसदेव पर आधारित जल संसाधनों का निरीक्षण करने के लिए टीम के सदस्य बांगो पहुंचे। यहां करीब एक घंटे तक टीम ने विभिन्न पहलुओं की जानकारी एकत्रित की। दर्री पहुंचे टीम के सदस्य बांध के निचले हिस्से में भी उतरे और जलभराव व जल छोड़े जाने का ब्यौरा लिया। हसदेव बांगो बांध वर्ष 1992 में बनकर तैयार हुआ। इसका जलस्तर 359.66 मीटर रहता है। इसके पहले 1964.65 में दर्री बराज बनकर तैयार हो गया था।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

उपराष्ट्रपति आज मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर आयेंगे

इम्फाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचेंगे और इस दौरान वह दो विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धनखड़ के धनमंजुरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक कार्यक्रम में भाग और बाद में परिसर में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि इसके बाद वह मणिपुर विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां वे विभिन्न संस्थानों के संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, ''उपराष्ट्रपति के हथकरघा और हस्तशिल्प/राज्य के जीआई टैग वाले उत्पादों के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं से भी मिलने की उम्मीद है।'' एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धनखड़ के दौरे के मद्देनजर राज्य की राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र

बेंगलुरु। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु के एक होटल में पार्टी का कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र जारी किया। उनके साथ राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी थे। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसे उसने 'सर्व जनांगदा शान्तिय तोटा' नाम दिया है। 'सर्व जनांगदा शान्तिय तोटा' का हिन्दी में अर्थ 'सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा' है। चुनाव घोषणापत्र के बारे में बोलते हुए, राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा, यह हमें बहुमत हासिल करने में मदद करेगा क्योंकि यह जन-केंद्रित है। यह कर्नाटक को वैश्विक कर्नाटक के रूप में ब्रांड करेगा। हम बेंगलुरु में ट्रैफिक को कम करने की कोशिश करेंगे और 2 और 3 टियर शहरों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे।

कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हिमंत ने किया कटाक्ष

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस घोषणा पत्र में फ्री बिजली, फ्री अनाज और बेरोजगारी भत्ते समेत कई वादे किए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है। कांग्रेस की इस मांग पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र दर्शाता है कि यह पूरी तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों का घोषणापत्र है। उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना जिंदा होते तो वह भी ऐसा घोषणापत्र नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बन गई है। सीएम बिस्वा ने कहा कि हमारे गृहमंत्री ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था। मंगलवार को कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने का वादा किया है।

शराब घोटाले की चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में आप सांसद राघव चड्ढा के नाम का उल्लेख किया। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि राघव चड्ढा के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक हुई थी। सी अरविंद के बयान के अनुसार बैठक में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रूजम, मामले के आरोपी विजय नायर और पंजाब आबकारी निदेशालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मनीष सिसोदिया को दिल्ली में सीबीआई अदालत के समक्ष दायर पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामित किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। सिसोदिया को फरवरी में जांच एजेंसी ने मामले के सिलसिले में आठ घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया।

हमने सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, तुष्टिकरण पर नहीं : योगी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ने तुष्टिकरण नहीं, बल्कि सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है, सब का विकास किया है। महापौर पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी उमेश चंद्र गणेश केसरवानी के पक्ष में शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लीडर प्रेस ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'आज उत्तर प्रदेश, परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के दलों से आगे बढ़कर एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।' उन्होंने कहा, 'पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता गणेश केसरवानी को महापौर का प्रत्याशी बनाना यह साबित करता है कि भाजपा नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही देश का लोकतंत्र है और भाजपा का लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह वही उत्तर प्रदेश था जहां पर्व और त्योहार भय और आतंक के साये में मनाए जाते थे।

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बोले प्रधानमंत्री- कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहने की जरूरत

कांग्रेस का इतिहास आतंकवादियों और आतंक के तुष्टिकरण का है : मोदी

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार, 2 मई को चित्रदुर्ग में रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आतंकियों का हमदर्द होने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टिकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया।

उन्होंने आगे कहा, प्रदेश भाजपा की टीम को, कर्नाटक भाजपा के नेतृत्व को आज मैं सार्वजनिक रूप से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। सोमवार को जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। इन दोनों दलों की प्राथमिकता कर्नाटक का विकास नहीं है।

कांग्रेस-जेडीएस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस-जेडीएस के कुशासन का प्रमाण है-अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनको किसानों की चिंता नहीं थी

इसलिए इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसके लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

कर्नाटक के लिए जारी घोषणापत्र में राज्य के लिए योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भाजपा ने योजनाओं का सुरक्षा घेरा तैयार किया है। पहला सुरक्षा घेरा- पक्के घर, मुफ्त गैस कनेक्शन, हर घर जल का है। दूसरा सुरक्षा घेरा- गरीबों को मुफ्त राशन, भुखमरी से बचाव और पोषण का है। तीसरा सुरक्षा घेरा- आरोग्य का है, मुफ्त इलाज और टीकाकरण का है। चौथा सुरक्षा घेरा- जनधन योजना और मुद्रा योजना के तहत दी गई लाखों करोड़ रुपये की मदद का है। पांचवा सुरक्षा घेरा- संकट के समय मदद का है, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना जैसे कवच का है। छठा सुरक्षा घेरा- बेहतर कानून व्यवस्था का है। सातवां सुरक्षा घेरा- हर समाज के हक को सुरक्षित करने का है।

कर्नाटक को हमें विकसित भारत की ड्राइविंग फोर्स बनाना है

मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर वन राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक विकास की किस उंचाई पर होगा।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक को हमें विकसित भारत की ड्राइविंग फोर्स बनाना है, ग्रोथ इंजन बनाना है। इसलिए भाजपा सरकार दोबारा बनाना है, डबल इंजन की सरकार को लाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र में कर्नाटक को देश का नंबर वन राज्य बनाने का रोड मैप है, इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लू प्रिंट है, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही हैं। मोदी ने कहा कि ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। इन दोनों दलों की प्राथमिकता कर्नाटक का विकास नहीं है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी भाजपा के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, भाजपा सरकार ने उससे दोगुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्षों में बना डाले।

कांग्रेस अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया

कर्नाटक में बजरंगबली को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होसपेट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को भगवान राम से दिक्कत थी और अब उसे 'जय बजरंग बली' कहने वालों से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य देखिए, मैं आज जब यहां हनुमान जी को नमन करने आया हूं उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के दशकों के शासन ने शहरों और गांवों के बीच खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, भाजपा सरकार गांव और शहर के बीच खाई को लगातार कम करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि आज हमारे गांवों के बीच शहरों जैसी सुविधा पहुंच रही है। गांव से जुड़ी दूसरी चुनौतियों का भी भाजपा सरकार समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की मान-मर्यादा और संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी।

शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान

मुंबई। महाराष्ट्र के वयोवृद्ध नेता शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष पद को छोड़ रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से एनसीपी में भारी गतिरोध चल रहा था। शरद पवार के भतीजे अजित पवार को लेकर काफी गहमागहमी मची थी। बताया जा रहा था कि अजित पवार पार्टी विधायकों का बड़ा हिस्सा तोड़कर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के साथ जा सकते हैं।

शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान अपनी आत्मकथा राजकीय आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर मुंबई में की। साल 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाने वाले उस वक्त से पार्टी के अध्यक्ष थे। ऐसे में उनके पार्टी अध्यक्ष पद से हटने के कई तरह के कयास लग रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पवार के बाद अब पार्टी की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले के पास जाती है या फिर उनके भतीजे अजित पवार एनसीपी की अगुवाई करेंगे।

शरद पवार ने आत्मकथा के अनावरण कार्यक्रम में कहा, मेरी इच्छा है कि अब इस पद को कोई और संभाले। इसलिए मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं। इस बीच खबर आ रही है कि पार्टी के नये अध्यक्ष के चुनाव के लिए समिति भी बन गई है। जिसमें प्रफुल्ल पटेल, अनिल देशमुख और दिलीप वलसे पाटिल सहित अन्य नेता शामिल हैं।

वहीं शरद पवार लगातार कह रहे थे कि वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ बने रहेंगे। पार्टी में उपजे विवाद को लेकर तब गंभीर कयास लगने लगे थे जब पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कुछ रोज पहले कहा था कि आगामी 15 दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है।

अब चूंकि शरद पवार ने अध्यक्ष पद से हटने कर दिया है तो उन दावों की पुष्टि होती है, जिसमें कहा जा रहा था कि शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच पार्टी के कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर खिंचतान चल रही थी। कहा जा रहा था कि अजित पवार अपने चाचा से बगावत करके कई विधायकों के साथ भाजपा का रुख कर सकते हैं।

इस संबंध में एनसीपी के नेताओं का कहना था कि शरद पवार इस टूट का बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अजित पवार ने पार्टी में या फिर शरद पवार के साथ किसी भी तरह के गतिरोध से इनकार करते हुए कहा था कि पार्टी में कोई भी असंतोष नहीं है और वह भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं।

हर किसी को समय के साथ लेना पड़ता है ऐसा फैसलाः अजित पवार

एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने समारोह में कहा कि हर किसी को समय के अनुसार उचित फैसला लेना होता है। अजीत पवार ने कहा, पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले बदलाव की जरूरत की बात कही थी। हमें उनके फैसले को उनकी उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए भी देखना चाहिए। हर किसी को समय के अनुसार निर्णय लेना होता है, पवार साहब ने निर्णय लिया है और वह इसे वापस नहीं लेंगे। अजित पवार ने आगे कहा कि पवार साहब (शरद पवार) हमेशा एनसीपी परिवार के मुखिया रहेंगे। जो भी नया अध्यक्ष होगा वह पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सलाह दी कि सुप्रिया सुले को शरद पवार से उनके फैसले पर बात करना चाहिए। हालांकि, अजित पवार ने सलाह दी कि सुप्रिया सुले को इस मामले पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। अजित पवार ने कहा, मैं उनका बड़ा भाई हूं इसलिए मैं उन्हें ऐसी सलाह दे रहा हूं।

खेल
प्रमुख समाचार

पंजाब किंग्स के सामने होगी मुंबई इंडियंस की कड़ी परीक्षा

मोहाली। पिछले मैच में अप्रत्याशित जीत के बाद अपना अभियान पटरी पर लाने के प्रयासों में जुटी मुंबई इंडियंस की टीम को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बुधवार को यहां होने वाले मैच में पंजाब किंग्स की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। मुंबई और पंजाब दोनों टीमों के लिए आगे के मैच काफी महत्वपूर्ण है। पांच बार का चैंपियन मुंबई पिछले सत्र में दसवें और आखिरी स्थान पर रहा था और इस बार भी उसकी स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम के आठ मैचों में आठ अंक है और वह सातवें स्थान पर है। ऐसे में एक हार से टीम के लिए आगे की राह कांटों भरी हो जाएगी। शिखर धवन की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की टीम के नौ मैचों में 10 अंक हैं और वह छठे स्थान पर है। वह इस मैच में जीत दर्ज करके प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत करना चाहेगी।

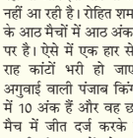

मुंबई का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में अंतिम ओवर में मिली जीत से मनोबल बढ़ा होगा। सिंगापुर में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड ने लगातार तीन छक्के जड़कर मुंबई को जीत दिलाई थी। उनकी 14 गेंदों पर खेली गई नाबाद 45 रन की पारी से राजस्थान रॉयल्स का सात विकेट पर 212 रन का स्कोर भी बौना साबित हो गया। भारत के टी20 विशेषज्ञ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (55), ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (44), इशान किशन (28) और तिलक वर्मा (नाबाद 29) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया लेकिन डेविड की पारी का कोई सानी नहीं था जिसमें उन्होंने पांच छक्के और दो चौके लगाए। मुंबई को अपने खिलाड़ियों से पंजाब किंग्स के खिलाफ इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। पंजाब की टीम आक्रामक क्रिकेट खेलती है लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चिंता शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 61,300 के ऊपर बंद निफ्टी 18,100 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले- जुले रुझान के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। घरेलू शेयर बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मंगलवार को हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 242 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में 83 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,147.65 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 242.27 अंक यानी 0.40 फीसदी मजबूत होकर 61,354.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 61,486.24 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 61,255.00 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (हस्थ) के निफ्टी में 82.65 अंक यानी 0.46 फीसदी की तेजी देखी गई। निफ्टी कारोबार के अंत में 18,147.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,180.25 की उंचाई तक गया और नीचे में 18,101.75 तक आया।

यूपीआई से लेन-देन का नया रिकॉर्ड

नईदिल्ली। अप्रैल में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से लेन-देन मूल्य के हिसाब से 14.07 लाख करोड़ रुपये और मात्रा के हिसाब से 8.9 अरब पर पहुंच गया है। इसमें मार्च के 14.05 लाख करोड़ रुपये और 8.7 अरब की तुलना में क्रमशः 0.14 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के अंतिम 3 दिन में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये के 1 अरब लेन-देन हुए हैं। अप्रैल 2022 की तुलना में पिछले महीने में लेन-देन मात्रा के हिसाब से 59 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 44 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल 2022 में 558 करोड़ से ज्यादा लेन-देन हुए, जिनका मूल्य 9.8 लाख करोड़ रुपये था। मार्च की तेजी के बाद यूपीआई से लेन-देन की गति अप्रैल में भी जारी रही।

अडाणी ग्रीन कंपनी का प्रॉफिट चार गुना बढ़ा

नईदिल्ली। अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से बड़ा नुकसान झेल रहे अदाणी ग्रुप के अच्छे दिन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे है। ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की चौथी तिमाही में तगड़ा मुनाफ़ा कमाया है। ग्रुप की इस कंपनी ने मार्च तिमाही में 507 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 121 करोड़ रुपये था, जो सालाना आधार पर 319 प्रतिशत उछलकर 507 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का रेवेन्यू भी एक साल पहले मार्च तिमाही में 1,587 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 2,988 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसमें करीब दोगुना वृद्धि हुई है। अच्छे नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वैसे कंपनी का शेयर फरवरी में अंत में 439.35 रुपये के साथ 52 हफ्तों के लो पर चला गया था।

सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 6,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,100 रुपये (50.14 डॉलर) प्रति टन कर दिया है। यह बदलाव मंगलवार से प्रभावी है। केंद्रीय संबंध और सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स 'जीरो' ही जारी रहेगा। इसका मतलब है कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट जारी रहेगी। बीते एक महीने में विंडफॉल टैक्स में तीन बार बदलाव हुआ है और वास्तव में विंडफॉल टैक्स को हर 15 दिन में बदला जाता है। इससे पहले चार अप्रैल को सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को पहले के 3,500 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया था। बाद में 19 अप्रैल को क्रूड पर टैक्स को बढ़ाकर 6,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।

कर्जदारों के हित में है आरबीआई का मसौदा परिपत्र

नारायण कृष्णमूर्ति

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्तीय सेवाओं में नियामक अक्सर बहुत देर से अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मसौदा परिपत्र जारी किया है-निष्पक्ष ऋण व्यवस्थाः ऋण खातों में दंड। इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं, जैसे बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं को प्रतिबंधित करना है, जिन्हें दिए गए ऋणों के देर से भुगतान पर दंडात्मक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।

अभी इन सभी संस्थानों के पास कोई मानकीकृत नियम नहीं है कि उधारकर्ताओं द्वारा देरी या चूक के मामले में वे दंड स्वरूप कितना शुल्क ले सकते हैं। संस्थाओं को यह निर्धारित करने की स्वतंत्रता है कि जब तक ऐसी उधार देने वाली कंपनियों के बोर्ड द्वारा दंड को मंजूरी दी जाती है, तब तक वे जितना चाहे जुर्माना लगा सकते हैं। अक्सर, दंड शुल्क एक समान नहीं होता है, लेकिन ब्याज के रूप में लगाया जाता है, जो अक्सर एक उधारकर्ता के लिए बहुत कठोर होता है, जो पहले से ही ऋण चुकौती के लिए संघर्ष कर रहा होता है।

उदाहरण के लिए, 1,000 रुपये की मासिक ईएमआई (किस्त) को लें, यदि ऋण पर ब्याज दर 10 फीसदी है और ब्याज की दंडात्मक दर एक फीसदी प्रति माह है, तो मूल रूप से देरी या चूक होने पर प्रति माह एक फीसदी जुर्माना कुल बकाया ऋण पर होगा, न कि सिर्फ ईएमआई पर, जो कि 1,000 रुपये है। यह व्यवस्था किसी भी उधारकर्ता के लिए बहुत महंगी साबित होती है और उनके लिए अनुचित है। जुर्माना एक निश्चित राशि होनी चाहिए और ईएमआई की मात्रा के आधार पर शुल्क बढ़ने के साथ ईएमआई रेंज के आधार

पर अलग-अलग होनी चाहिए। हालांकि देर हो चुकी है, लेकिन अंततः भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र में इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि ऋण देने वाली संस्थाएं लागू ब्याज दरों से बहुत ज्यादा ब्याज की दंडात्मक दर वसूलती हैं, अगर उधारकर्ता ऋण स्वीकृति के समय लागू शर्तों को पूरा करने में चूकते हैं या उनका गैर-अनुपालन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को उधारदाता वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाए गए इस तरह के किसी भी भारी जुर्माने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यह एक रहस्य है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक निगरानीकर्ता है, जिसे ये संस्थाएं रिपोर्ट करती हैं और उसे इस तरह के अनाचार के बारे में पता होना चाहिए था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र में शुल्क के मानकीकरण के लिए कहा गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि जुर्माना उधारकर्ताओं को गलती का एहसास कराने के लिए है और इसे हालात के मौद्रीकरण के तरीके के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्कूल फीस या फोन बिल के देर से भुगतान के लिए लगाए जाने वाले विलंब भुगतान शुल्क के बारे में सोचें, जो स्थिर प्रकृति के होते हैं और बीच में उनमें अंतर नहीं होता। इसके अलावा ये सभी के लिए एक समान होते हैं। ऋण के मामले में दंड न केवल विभिन्न उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग होता है, बल्कि एक ऋणदाता से उधार लेने के आकार के अनुसार भी भिन्न होता है। इसलिए, एक आवास ऋण लेने वाले छोटे स्तर के उधारकर्ता की तुलना में एक कॉरपोरेट संस्था पर ऋण चुकाने में देरी करने पर अपेक्षाकृत कम दंड (उनके बकाया ऋण के आधार पर) लगाया जाता है। यह विसंगति अनुचित प्रथाओं के समान है और बड़े कर्जदारों को भुगतान में चूक करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उन्हें सख्त कार्रवाई या भारी मौद्रिक दंड का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में कोई भी अनुमान लगा सकता है कि विजय माल्या जैसे बड़े कॉरपोरेट कर्जदारों ने किस तरह न केवल बैंक का भारी-भरकम कर्ज नहीं चुकाया; बल्कि वे विदेश में भी आरामदायक जीवन जी रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ब्याज दरों के पुनर्गठन के लिए शर्तों सहित ऋण सुविधाओं पर ब्याज दरें, जारी किए गए प्रासंगिक नियामक निर्देशों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होंगी और ऋण देने वाली संस्थाएं ब्याज दर के लिए कोई अतिरिक्त घटक पेश नहीं कर सकती हैं।

क्या कर्नाटक से खुलेंगे आम चुनाव के पत्ते?

नरेन्द्र नाथ

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जैसा हाई वोल्टेज घमासान देखने को मिल रहा है, वह सिर्फ प्रदेश की सत्ता हासिल करने को लेकर नहीं है। इस चुनाव में दोनों दल जिस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भी परीक्षा होनी है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 10 मई को होनी है और परिणाम 13 मई को आएंगे। माना जा रहा है कि जिस दल का प्रयोग सफल होगा, उसका असर आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों से लेकर अगले साल होने वाले आम चुनाव पर भी देखा जाएगा। कांग्रेस ने इस बार चुनाव के बीच कर्नाटक में नया सामाजिक प्रयोग किया है। चुनाव के दौरान ही पार्टी ने जाति जनगणना की मांग के अलावा आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से अधिक करने का वादा किया। राज्य के पूर्व सीएम और पार्टी के सीनियर नेता सिद्धारमैया अब हर सभा में आरक्षण की सीमा को 75 फीसदी तक करने की बात दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी भी राज्य में हो रही सभाओं में आक्रामक रूप से ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। दिलचस्प बात है कि मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी 2019 में कर्नाटक में ही सामने आई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर ओबीसी के अपमान का आरोप लगा रही है। पार्टी के इस सामाजिक प्रयोग के पीछे उसकी अपनी राजनीतिक गणना है। राज्य में जातियों के समीकरण बहुत मायने रखते हैं और इसमें सभी का पहले से ही अपना-अपना हिसाब-किताब रहा है।

जहां तक इस चुनाव की बात है, वोक्कालिगा समुदाय इस बार जेडीएस के साथ दिख रहा है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस को बहुत छोटा हिस्सा मिलने की संभावना है। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम और ईसाई वोट उसे एकमुश्त मिलेगा। लिंगायत वोट में कांग्रेस जरूर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जो भी वोट आएगा- वह बोनस ही होगा क्योंकि लिंगायत समुदाय के लोग बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट करते रहे हैं। ऐसे में पार्टी को वोट का बड़ा हिस्सा ओबीसी से ही मिलने की उम्मीद है। सिद्धारमैया खुद ओबीसी नेता हैं। इसके अलावा 'जिसकी जितनी आबादी, उसको उतना हक' के दांव से कांग्रेस दलितों को भी अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इस चुनाव में यह दांव सफल रहा तो आम चुनाव तक इसी रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाएगा। हाल के सालों में पूरे देश में बीजेपी की बड़ी सियासी जीत के पीछे ओबीसी वोट का बड़ा योगदान रहा है। नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी नेता के रूप में जनता के बीच पेश करते हैं। इस प्रयोग से पार्टी को इसकी काट भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके अपने जोखिम भी हैं। पार्टी जितने आक्रामक रूप से ओबीसी राजनीति करेगी, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग करेगी, सवर्ण वोट पार्टी से छिटकते जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अभी भी सवर्णों के वोट पार्टी को ना के बराबर मिल रहे हैं। ऐसे में इस प्रयोग से कुछ वोट बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। बीजेपी ने भी इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक खास राजनीतिक प्रयोग किया है। यह प्रयोग कमोबेश गुजरात मॉडल की तर्ज पर है। इसके तहत पार्टी चुनाव के दौरान ही पुराने नेतृत्व के मुकाबले नए नेतृत्व को सामने करती है। कुछ वक्त पहले पार्टी ने इसी मंशा से येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाकर एसआर बोम्मई को वहां का मुख्यमंत्री बनाया था। पार्टी ने टिकट वितरण में भी यही ट्रेंड कायम रखा। पूर्व सीएम और छह बार के विधायक जगदीश शेट्टार तक को पार्टी ने चुनाव में टिकट नहीं दिया। इस कारण शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। लिंगायतों में शेट्टार का भी असर है। इसी तरह पार्टी ने दूसरे कुछ दिग्गजों को टिकट दिए। पार्टी ने संदेश दिया कि राज्य में वह नए नेतृत्व और नई पीढ़ी के साथ चुनाव में हैं। इसके पीछे बीजेपी की दोहरी सोच है। पहली, इससे वह एंटी इनकंबेंसी फैक्टर को काउंटर कर लेगी। और दूसरी, पुराने और उम्रदराज हो रहे नेतृत्व के रहते हुए नया नेतृत्व खड़ा कर लेगी, ताकि आने वाले दिनों में भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए रख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने यह प्रयोग पिछले दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक किया था। अब यही प्रयोग इस बार कर्नाटक में हो रहा है।

दक्षिण में भाजपा की रणनीति

मृत्युंजय दीक्षित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में उत्तर, पश्चिम तथा पूर्वोत्तर भारत में अपनी जड़ें जमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब दक्षिण की ओर रुख किया है। भाजपा दक्षिण के राज्यों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है लेकिन उसे अभी तक कर्नाटक को छोड़कर किसी और दक्षिणी राज्य में उल्लेखनीय सफलता अर्जित नहीं हो पाई है। इस बार दक्षिण के लिए भाजपा के तेवर तीखे और विजय की अभिलाषा वाले हैं। पार्टी इस बार मोदी के नेतृत्व में नई रणनीति के साथ दक्षिण भारतीयों का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दक्षिण के राज्यों के सघन दौरे कर रहे हैं।

केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोच्चि व तिरुअनंतपुरम शहरों में आयोजित रोड शो में जिस प्रकार आम जन उमड़ पड़ा, उन पर पुष्पवर्षा की तथा मोदी-मोदी के नारे लगाए उसे देखकर यह लग रहा है कि आने वाला समय केरल व दक्षिण के राज्यों में भी भाजपा का हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दक्षिण मिशन को केवल चुनावी दृष्टिकोण से ही नहीं हो रहा है अपितु एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार की स्थापना के लिए भी हो रहा है। इससे दक्षिण भारत में भाषा समस्या, उत्तर दक्षिण विभाजन, बदलती जन सांख्यकी, धर्म परिवर्तन, राजनीति में परिवारवाद, भ्रष्टाचार आदि पर आम जन को विश्वास में लेकर प्रहार किया जा सकेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा विकसित भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने अपनी केरल की दो दिवसीय यात्रा में कई कार्यक्रमों में भाग लिया, कोच्चि में उन्होंने युवाओं के कार्यक्रम को संबोधित किया जबकि तिरुअनंतपुरम में वंदे भारत मेट्रो की सौगात दी। केरल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पादरियों से मुलाकात की जिससे सेक्लयुर बिरादरी के माथे पर पसीना आ गया। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिर परिचित अभ्यास है वो जिस प्रान्त में जाते हैं वहीं के परिधान और परंपरा को अपना लेते हैं उन्होंने अपनी केरल यात्रा के दौरान केरल केरल के पारंपरिक परिधान में ही सारे कार्यक्रम और यात्रा संपन्न की। उन्होंने केरल की जनता को वंदे भारत एक्सप्रेस, वाटर मेट्रो सहित विकास योजनाओं के कई उपहार दिए, तिरुअनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 3200 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का संबोधित करते हुए केरल के लिए भविष्य की राजनीति की योजना भी बता दी। उन्होंने राज्य में हो रहे घोटालों तथा भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि केरल सरकार व यहां के सभी दल युवाओं के भविष्य के छल कर रहे हैं। केरल सरकार युवाओं के लिए न तो रोजगार मेला आयोजित करती है और न ही सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती विज्ञापन निकालती है जबकि जहां-जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर युवाओं के लिए रोजगार मेलों तथा सरकारी नौकरियों की बयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा हमेशा युवाओं के साथ रहेगी जबकि पारंपरिक मोर्चे युवाओं की भलाई का कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दो पारंपरिक राजनीतिक मोर्चों के बीच वैचारिक मतभेद के कारण केरल में युवाओं ने बहुत सारे अवसर खो दिए। एक पार्टी ने अपने विकास को प्राथमिकता दी तो वहीं दूसरे दल ने परिवारवाद को और दोनों ने ही युवाओं को फेल कर दिया। युवाओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि आज देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और आप सभी युवा केरल का एक नया इतिहास लिखें और उसका नेतृत्व करें मैं आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूं।

केरल हवाई अड्डे पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और दोनों नेता एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए, उनका यह चित्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस चित्र के सामने आने के बाद राजनैतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में शशि थरूर भी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थाम सकते हैं। केरल में अपनी राजनैतिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है और यही कारण है कि भाजपा ने महान धाविका पीटी ऊषा को राज्यसभा में मनोनीत किया है। केरल व दक्षिण के राज्यों में ईसाइयों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके तमाम आनुषांगिक संगठनों का भी सहयोग प्राप्त कर रही है। अभी अल्पसंख्यक पर्वों- गुड फ्राइडे आदि के अवसर पर राष्ट्रीय ईसाई मंच की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। संघ के कई पदाधिकारी पादरियों से मिलने गये व विभिन्न विषयों व समस्यायों चर्चा भी हुई। ईसाइयों के बीच भाजपा की छवि को सुधारने के लिए ही प्रधानमंत्री 8 ईसाई पादरियों से भी मिले।

केरल में 18 प्रतिशत ईसाई और 28 प्रतिशत मुस्लिम तथा 54 प्रतिशत हिंदू हैं। प्रधानमंत्री ने केरल वासियों से कहा कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में नागालैंड, मेघालय व त्रिपुरा में कमल खिला है और बार-बार खिल रहा है तथा वहां के अल्पसंख्यक समाज ने जिस प्रकार सभी राजनैतिक अवधारणाओं को बदल कर रख दिया है उससे उनका यह संकल्प और मजबूत हो गया है कि आगामी समय में केरल में भी कमल खिलेगा और सभी अवधारणाओं को विफल करेगा।

प्रधानमंत्री दक्षिण में भाजपा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इससे पूर्व वे तमिलनाडु और तेलंगाना का भी तूफानी दौरा कर आये हैं। इसी वर्ष तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और वहां पर भी वह वंदेभारत सहित हजारों करोड़ की योजनाओं का उपहार देकर आये थे। प्रधानमंत्री व बीजेपी के ताजा प्रयासों से दक्षिण की राजनीति में एक नई चमक व उत्तेजना दिखाई पड़ रही है। बीजेपी व संघ की बढ़ती लोकप्रियता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन घबरा रहे हैं तो केरल व कर्नाटक के वामपंथी और कांग्रेसी भी। तमिलनाडु सरकार ने भाजपा व संघ की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथसंचलन को रोकने का असफल प्रयास किया और स्टालिन अपने ही दांव में घिर गये। प्रधानमंत्री के नेतृत्व व उनके मार्ग निर्देशन में काशी से लेकर गुजरात में तमिल संगमम जैसे आयोजन किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री की ताजा दक्षिण यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि जिस राज्य में कभी भाजपा को एक कार्यकर्ता तक खोजे नहीं मिलता था, उसी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने व सुनने के लिए लाखों की उत्साहित भीड़ आ रही है। केरल का जनमानस अच्छी तरह से समझ रहा है कि आज भारत का भविष्य प्रधानमंत्री रेंद्र मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है तथा वही राज्य को घोटालों और मुगलिया संस्कृति से आजाद करा सकते हैं। अब केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा की बढ़ रही लोकप्रियता के कारण अन्य विचारधारा वाले दलों का साथ भी मिलने लगा है। अभी बीबीसी विवाद के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थामा।

प्रधानमंत्री, भाजपा व संघ की बढ़ती लोकप्रियता के कारण दक्षिण के परिवारवादी नेता एक बार फिर हिंदी विरोध पर उतर आये हैं। उनको लगता है कि संघ के पथसंचलन पर बैन लगाकर, हिंदी को गाली देकर व अपमानित करके ही दक्षिण में भाजपा की बढ़त को रोका जा सकता है किंतु अब यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का मन बदल रहा है।

अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनावों से यह साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी का दक्षिण विजय का अभियान कितना सफल हो रहा है। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव एक लिटमस टेस्ट होगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि कर्नाटक में बहुत कांटे की टक्कर हो रही है किन्तु यदि भाजपा सरकार बनाने में चूक भी जाती है तो भी उसका मतलब यह नहीं होगा कि बीजेपी का मिशन दक्षिण फेल हो गया अपितु वह और अधिक मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अब प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के संकल्प को रोकना कठिन होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

शाण्डिल्योपोनषद् (भाग-17)

गतांक से आगे...

इसके अनन्तर वह आत्मा क्यों कहा जाता है? (ऐसा पूछने पर अथर्वा मुनि ने कहा-) वह (ब्रह्म) सर्वत्र सभी में विद्यमान रहता है, सभी को स्वीकार करता है तथा सभी का भक्षण कर लेता है अर्थात अपने में मिला लेता है, इस कारण वह आत्मा कहलाता है।

वह महेश्वर क्यों कहा जाता है? (अथर्वा मुनि ने कहा-) क्योंकि वह शब्द ध्वनि एवं आत्मशक्ति से बड़ों-बड़ों का नियंत्रण करता है तथा बड़ों-बड़ों का ईश्वर है, इसलिए वह महेश्वर कहलाता है।

वह दत्तात्रेय क्यों कहा जाता है? (अथर्वा मुनि ने उत्तर दिया) क्योंकि अत्यन्त उग्र तपश्चर्या करने के उपरान्त अत्रि ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। तदनन्तर उनके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हुए ज्योतिष्मान् भगवान् (शिव) ने स्वयं को ही उन अत्रि ऋषि को पुत्र रूप में प्रदत्त किया और वे स्वयं अत्रि एवं अनसूया के द्वारा प्रादुर्भूत हुए । इस प्रकार से वे दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए।

अथ योऽस्य निरुक्तानि वेद स सर्व वेद। अथ यो ह वै विद्यवैनं परमुपास्ते सोऽहमिति इन समस्त अर्थ सहित नामों को जो व्युत्पत्ति सहित समझता है, वह सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। इसके अनन्तर जो (इस आत्म) विद्या के द्वारा इस परमात्म तत्त्व की उपासना करता है, वह मैं ही परमात्मा हूँ इस प्रकार के भाव से ब्रह्म का वर्णन करने वाला (ब्रह्मवेत्ता) बन जाता है।

यहाँ पर ये निम्न लोक कहे गये हैं- मंगल स्वरूप वाले, शान्तरूप वाले, इन्द्रनीलमणि के समान श्याम, आत्ममाया के साथ रमण करने वाले, अवधूत, नग्न शरीर वाले, भस्म लगे हुए शरीर वाले, जटाजूट धारण किये हुए, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, चार भुजाओं से युक्त, उदार अंग वाले, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले, ज्ञानयोग के भण्डार, सम्पूर्ण विश्व के गुरु योगी जनों के प्रिय, अपने भक्तजनों पर दया करने वाले, सबके साक्षी एवं सिद्धजनों द्वारा सेवित प्रभु दत्तात्रेय देव शाश्वत, सनातन पुरुष हैं तथा देवों के भी देव अर्थात् आदिदेव हैं। इस तरह से जो पुरुष निरन्तर सदा ही उन (देवपुरुष) का ध्यान करता रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इति ? सत्यम् अर्थात् यही सत्य है। इस प्रकार से यह उपनिषद् (रहस्यमयी विद्या) पूर्ण हुई। **क्रमशः...**

अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस

दीपक कुमार त्यागी

खींचो न कमानों को न तलवार निकालो,
जब तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो।

उन्होंने शायर के रूप में लगभग सौ वर्ष पहले ही प्रेस की ताकत का अंदाजा लगा लिया था, वास्तव में यह बात एकदम कटु सत्य है, आज के दौर में भी निष्पक्ष व निर्भीक कलम की ताकत के आगे तलवार और तोप की ताकत कोई मायने नहीं रखती है। किसी देश में जो अहिंसक तरीकें से शांतिपूर्ण ढंग से बड़ा बदलाव प्रेस ला सकती वो और किसी भी और माध्यम से लाना संभव नहीं है। वैसे भी भारत जैसे 135 करोड़ लोगों की भारी-भरकम जनसंख्या वाले देश में हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए प्रेस के सभी संस्थानों व कलमकार की स्वतंत्रता व निष्पक्षता बेहद जरूरी है। उनका देश व समाज के प्रति सकारात्मक व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी है।

हालांकि आज के व्यवसायिक दौर में हावी होते बाजारवाद के मूल्यों से प्रेस भी बहुत अधिक प्रभावित हुई है, प्रेस के संस्थानों की जबरदस्त आपसी व्यवसायिक आपाधापी वाली प्रतिस्पर्धा के चलते, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर तो कम लेकिन कुछ संस्थानों की निष्पक्षता पर बार-बार देशवासियों के द्वारा प्रश्नचिन्ह जरूर लगाया जा रहा है।

भारत के साथ सम्पूर्ण विश्व में 3 मई के दिन को अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का मकसद था कि लोग विश्व में स्वतंत्र व निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करके, वो प्रेस के हितों की रक्षा करें। आज के आधुनिक समय में भी प्रेस को किसी भी राष्ट्र या समाज के बारे में जानने का सबसे विश्वसनीय सशक्त माध्यम या आईना माना जाता है, जो किसी भी राष्ट्र या समाज के हालातों की और हर प्रकार की सम-सामयिक परिस्थितियों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करके सटीक विश्लेषण करता है। प्रेस की स्वतंत्र स्थिति के बारे में बेहद आसान शब्दों में समझें, तो किसी भी देश में प्रेस की आजादी इस बात से ही साबित हो जाती है कि उस देश में लोगों को बोलने की कितनी आजादी है, उन्हें सिस्टम में बैठे ताकतवर लोगों के सामने अपनी बात उठाने के लिए अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले विशाल देश में, प्रेस की स्वतंत्रता व निष्पक्षता एक मौलिक जरूरत है।

अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के इतिहास की बात करें तो सन् 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय किया था। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में सन् 1993 में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों की गंभीरता के बारे में जानकारी देना है। इसके उद्देश्यों में प्रकाशनों की कांट-छांट, उन पर जुर्माना लगाना, प्रकाशन को निलंबित कर देना और बंद कर देना आदि भी शामिल है। विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि बीते वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर-सरकारी संगठन के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। जो कि विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इस सूचकांक पर देश में पत्रकारिता के धुरंधरों के तरह-तरह के मत है कोई इसके पक्ष में है कोई इसके विपक्ष में खड़ा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस तरह से भारत में अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी है, उसी तरह से प्रेस को भी पूर्ण आजादी प्रदान है। कही ना कही यह सूचकांक हमारे देश व देश की प्रेस के प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आता है।

अपराधियों से अटी पड़ी हमारी संसद

शशांक खरे

लोकसभा में 42 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं, राज्यसभा में 31 प्रतिशत सांसदों पर केस चल रहा है। है ना चौंकाने वाली बात। लेकिन, चौंकिए नहीं। भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप अब कुछ ऐसा ही बदलता जा रहा है, जहां साध्य महत्वपूर्ण है, साधन नहीं। कभी ये कहा जाता था, कि मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान।।।अब ये बातें दकियानूसी और अटपटी सी लगती हैं। नया युग है, नया जमाना है। भारतीय लोकतंत्र की अहमियत, भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, भारतीय बुद्धिजीवियों का मंतव्य बीते कल की बात हो गई। अब तो वो दौर आ गया है, जहां नैतिकता केवल कहने की चीज है।

राजनीति में अपराधीकरण रोकने की बात बातें चल रही हैं। चुनाव आयोग ने हाल में संसद में आपराधिक चरित्र के जनप्रतिनिधियों के जमावड़े पर चिंता जताई है। आयोग ने आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर होने तथा आरोप तय होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। आयोग का कहना है कि वह राजनीति को पूरी तरह से अपराधमुक्त करना चाहता है, वह इसके पक्ष में है, मगर आपराधिक छवि के नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक पाना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यानी संसद में इसके लिए कानून बनाने की उन्होंने वकालत की है।

हाल ही में मीडिया के प्रकाश में आई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हमारी दोनों ही सभाएं

(लोकसभा और राज्यसभा) अपराधियों का गढ़ है।

लोकसभा में 542 सांसदों में से 233 यानी 43 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। 233 में से 159 यानी 29 प्रतिशत पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। ऐसे सांसदों में से सबसे अधिक केरल और बिहार में से हैं। केरल में इडुक्की लोकसभा के सांसद कुरियाकोस पर सबसे अधिक 204 केस दर्ज है। वहीं राज्यसभा की 233 में से 71 यानी 31 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक केस लंबित है। 71 में 37 सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले, 2 पर हत्या, 4 पर हत्या का प्रयास, 3 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, 1 पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। 106 सांसदों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनआईए के समक्ष मामले दर्ज हैं। सीबीआई के पास 121 पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के मामले लंबित है। इनमें से 51 मामले सांसदों से संबंधित हैं। इन 51 में से 37 पूर्व सांसद हैं और पांच की मौत हो चुकी है। एनआईए के पास 4 सांसद और विधायकों के खिलाफ जांच लंबित है। इनमें से दो सांसद हैं। ईडी का पास 51 सांसदों के खिलाफ जांच लंबित है।

एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करते हुए बताया था कि मोदी सरकार में शामिल 78 में 33 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। यानी, यह संख्या 42 फीसदी है। यहां यह तर्क दिया जाता है कि आपराधिक मामले दर्ज हैं या आरोप है, सिद्ध तो नहीं हुए ना? यही तो देश का दुर्भाग्य है। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया के प्रकाश में ये बात सामने आई कि, 24 या 31 फीसदी मंत्रियों ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती से संबंधित सहित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। यह भी बात सामने आई है कि मोदी सरकार के मंत्रियों में 70 यानी 90 फीसदी करोड़पति हैं। प्रति मंत्री औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपए है। चार मंत्रियों ने 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, नारायण राणे और राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। धनकुबेरों का संसद में पहुंचना हमारी समृद्धि का सजीव उदाहरण है, जो कि देश के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात तो तब और अधिक होगी, जब धनकुबेर मंत्री, देश की शोषित, दलित, गरीब जनता को भी उनके हाल से उबारकर धनकुबेर बना देंगे। वरना, देश में अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई किसी से छुपी नहीं है। एक ओर धनकुबेरों का संसद में जाना और मंत्री बनना, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया में हर एक मिनट में 11 लोगों की भूख से मौत का डरावना सच भी हमारे सामने है। जिस विशाल लोकतंत्र की दुनिया में एक मिसाल कायम है, उसी लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में आपराधिक छवि के जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या चुगली भी करती है। आरोप सिद्ध नहीं तो कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाहगार नहीं। भारतीय संविधान में इतने सारे रास्ते हैं, कि कहीं से भी बचकर निकला जा सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वकील दागदार छवि से वैसा ही समाज बनता है, जैसी छवि होती है। अतः साध्य के साथ पर साधन की पवित्रता पर भी ग़ौर करने की जरूरत है।

बापू की दिनचर्या

प्रातःकालीन प्रार्थना

उनके अनुसार प्रार्थना से अंतरात्मा की पुकार परमात्मा तक पहुँच जाती है। प्रार्थना में ईश्वर से होने वाले सहकार से हृदय का स्नान हो जाता है। जिस प्रकार स्नान या स्वच्छता के बिना शरीर मलीन बना रहता, उसी प्रकार प्रार्थनारूपी जल के बिना मलरहित आत्मा मलीन हो जाती, किंतु प्रार्थना हार्दिक-हृदय या मन से होनी चाहिए, अन्यथा उससे पूरा लाभ नहीं मिल सकता। बापू व्यक्तिगत प्रार्थना पर भी बहुत बल देते। सामूहिक प्रार्थना से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना को वे बहुत जरूरी मानते। उनकी मान्यता थी कि जिस तरह व्यक्ति से समाज बनता, उसी तरह व्यक्तिगत प्रार्थना से सामूहिक प्रार्थना संभव है। वे व्यक्तिगत प्रार्थना को सामूहिक प्रार्थना का मूल मानते और उसे सामूहिक प्रार्थना से अधिक महत्व देते।

बापू की सामूहिक प्रार्थना ने कोटि-कोटि मानव समूह को जो शक्ति और प्रेरणा दी, वह वर्णनातीत है। उनकी हम सब (हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई - सभी धर्मावलंबियों) को यह नई देन है। उनकी प्रार्थना में सब धर्मों की उपासना एवं प्रार्थना सभा में सभी धर्मानुयायियों को सम्मिलित होते देख प्रायः कुछ लोगों को आश्चर्य होता, घबराहट और परेशानी भी होती; परंतु बापू समन्वयवादी थे; अतः अपने लक्ष्य पर अटल रहते। नोवाखाली यात्रा के समय वहाँ के दूषित वातावरण में वे अक्सर मुसलमान भाइयों के यहाँ ठहरते और वहाँ अपनी दैनिक प्रार्थना करते। मसजिद के अहाते (अंदर के मकान) में प्रार्थना के अवसर वहाँ आते और वहाँ तालियों के साथ %रामधुन% होती। वे महामानव थे। उनमें संकीर्णता का अंश तनिक नहीं था। यही कारण है कि साधारण ज्ञानवालों के लिए वे पहेली थे।

बापू का कहना था कि सत्य का आग्रह अगर आश्रम के मूल में है तो प्रार्थना उस मूल की बुनियाद है। इसी कारण उनके आश्रम में आरंभ से प्रार्थना से कार्य का श्रीगणेश और प्रार्थना से उसका समापन होता। वे प्रार्थना को सुबह की कुंजी और शाम की चटकनी समझते। बापू की प्रार्थना प्रायः खुले मैदान में होती। उन्होंने आश्रम में प्रार्थना के लिए कभी किसी भवन का निर्माण नहीं कराया।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री आज करेंगे छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 03 मई को 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल और मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा होंगे। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ समारोह प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ प्लांट साइंस रिसर्च नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो. प्रवीनचंद्र त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ कॉउन्सिल ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल डॉ. एस. कर्माकर अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला करेंगे।

मरकाम 6 को बस्तर व 10 को लेंगे सरगुजा संभाग की करेंगे समीक्षा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 6 मई को सुबह 11 बजे राजीव भवन जगदलपुर में बस्तर संभाग तथा 10 मई को सुबह 11 बजे राजीव भवन अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के सभी जिला, शहर, नगर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी पदाधिकारी की बैठक लेकर बूथ-सेक्टर-जोन कमेटियों के गठन की समीक्षा करेंगे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. चंदन यादव एवं प्रभारी बूथ प्रबंधन कमेटी अरुण सिसोदिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में प्राप्त आवेदनों पर दावा आपत्ति आमंत्रण

कांकेर। छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में प्राप्त आवेदनों पर दावा आपत्ति आमंत्रण एवं निराकरण किए जाने हेतु ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। त्रुटि रहित सर्वेक्षण एवं इसकी प्रमाणिकता हेतु सर्वेक्षण की दस्तावेज संबंधी जानकारी संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन करने तथा जनसामान्य के समक्ष सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार सभी स्तरों से एडिटिंग की कार्यवाही पूर्ण करते हुए 5 से 15 मई तक सर्वेक्षण की जानकारी एवं निराकरण किया जायेगा। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों में 5 मई से 15 मई तक ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन सुनिश्चित किया जावे तथा अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिये हैं। कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए विशेष ग्राम सभा आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदाधिकारी सरपंच तथा पंचों को दी जावे जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों अस्थाई रूप से होगी भर्ती

कोरबा। जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षकों की अस्थाई रूप से नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 12 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी आदेशानुसार रिक्त पदों के अंतर्गत नवीन उम्मीदवार के साथ सेवा निवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

भगवान श्री नरसिंहनाथ प्रगट उत्सव 4 मई को

रायपुर। भगवान श्री नरसिंहनाथ प्रगट उत्सव चार मई गुरुवार को श्री बिरंचीनारायण नरसिंहनाथ मंदिर ब्रम्हपुरी में मनाया जायेगा। प्रगट उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 10 बजे दुग्धाभिषेक, दोपहर 12 बजे हवन, दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक भंडारा, शाम 5 बजे भगवान नरसिंहनाथ की शोभायात्रा, शाम 6.40 बजे हिरण्यकश्यप का संहार भगवान नरसिंहनाथ द्वारा, शाम 7 बजे महाआरती होगी। अध्यक्ष अजय तिवारी, उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद शुक्ला, सचिव वेदनारायण सिंह, ट्रस्टी एस के चंद्रवंशी, सरवराकार महंत देवदास, ट्रस्टी अनिल अग्रवाल, किशन जैन ने श्रद्धालुजनों से प्रगटउत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है।

डाटा कलेक्शन के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी को मिली राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

रायपुर। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में शहर विकास और जन सुविधाओं से संबंधित आँकड़े के बेहतर व उपयोगी संकलन के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इन उपलब्ध आंकड़ों के समुचित उपयोग से नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लागू किए जाने वाले नवाचारों का क्रियान्वयन सुगम हो सकेगा। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा बुनियादी जन सुविधाओं के उपयोग संबंधी ये आँकड़े एकत्र कर इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत सरकार को उपलब्ध कराए गए थे।

बख्शीजी ने बोझिल शब्दों से परहेज किया : जयप्रकाश

' निबंध की परम्परा और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ' विषय पर गोष्ठी आयोजित

भिलाई। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई नगर द्वारा भिलाई के सेक्टर 10 स्थित इंडियन कॉफी हाउस सभागार में डॉक्टर प्रमोद वर्मा स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत ' निबंध की परम्परा और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ' विषय पर गोष्ठी आयोजित की गयी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता वरिष्ठ समीक्षक डॉ .जयप्रकाश ने कहा कि बख्शी जी तरलता, सरलता और बौद्धिकता के बोझ से मुक्त थे। यह विशेषताएं उनके लेखन में भी दिखती हैं। उनके लेखन में रम्यता और रंजकता का समावेश है। उनका साहित्य उन्मुक्त और आत्म परक होने के साथ साथ भाषाई छल एवं वाग्जाल से परे है।

उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के बाद बख्शी जी जैसे रचनाकारों ने लेखन में बोझिल शब्दों से हमेशा परहेज किया। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉ जयप्रकाश ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि नयी पीढ़ी में निबंध लेखन को लेकर कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है , बल्कि

शून्यता का वातावरण है। उन्होंने ललित निबंधों पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी ,साथ ही निबंध परंपरा पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी जानकारी की पुष्टि की।

अध्यक्षीय भाषण में वरिष्ठ व्यंग्यकार रवि श्रीवास्तव ने कह कि डॉ. प्रमोद वर्मा ,चूंकि सृजनपीठ के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं ,उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाना सराहनीय है।उन्होंने बख्शी जी को ऋषि तुल्य रचनाकार निरूपित करते हुए पूर्व में आयोजित 'त्रिधारा' कार्यक्रम की चर्चा भी की। आयोजकीय वक्तव्य में बख्शी सृजन पीठ के अध्यक्ष ललित कुमार ने कहा कि व्याख्यानमाला डॉ. प्रमोद वर्मा की स्मृति को समर्पित एक ऐसा आयोजन है ,जिसमें यह प्रयास है कि निबंध परम्परा को आज की पीढ़ी जान- समझ सके ,बख्शी जी के निबंधों के बहाने बीसवीं सदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य की कमियों को उजागर करने में अन्य रचनाकारों के साथ-साथ डॉक्टर प्रमोद वर्मा का भी योगदान रहा है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अंबरीश त्रिपाठी ने और आभार व्यक्त व्यंग्यकार विनोद साव ने किया। आयोजन में वरिष्ठ लेखक कनक तिवारी, विजय वर्तमान ,डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव ,संतोष झांझी , डॉ अशोक सैमसंग ,आशा झा ,डॉ रजनीश उमरे, डॉ अभिनेष सुराना ,संध्या श्रीवास्तव, अनुराधा बख्शी ,डॉ.डीपी देशमुख, परमेश्वर वैष्णव, प्रदीप भट्टाचार्य, प्रदीप वर्मा ,मुमताज ,नरेश विश्वकर्मा ,के.डी. खरे, कल्याण सिंह साहू, बी. पी .तिवारी, शुचि ' भवि ' , शीशलता ' शालू ' मनीषा मुखर्जी ,बेलमती पटेल ,कमलेश वर्मा ,पुनू यादव ,हितेश साहू, सनत मिश्रा ,तेजस तिवारी, एन.एल .मौर्य सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल में कर्म एवं पाली शिरोमणि पुरस्कार समारोह का आयोजन

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र में शिरोमणि पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए कर्म एवं पाली शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी के तहत आरएसएम विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्री हेमंत कुमार चंद्राकर को पाली शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया तथा श्री करतार दहिया, मास्टर टेक्नीशियन एवं प्रवीण कुमार देशमुख, ओसीटी को कर्म शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह में महाप्रबंधक श्री एन के खरे, श्री एच आर मेघवाल, श्री सुनील सोरते एवं श्री अतुल दुबे श्री मलिक, श्री एस चट्टोपाध्याय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा कार्मिक उपस्थित थे। समारोह में मुख्य महाप्रबंधक (आरएसएम एवं आरटीएस) श्री तीर्थंकर दस्तीदार द्वारा स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं उनके जीवनसाथी के लिए प्रशंसा पत्र तथा मिठाई का कूपन देकर सम्मानित किया गया। शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी कर्मियों को बधाई देते हुए उनके कार्य के प्रति कर्मठ योगदान की प्रशंसा की। पुरस्कृत कार्मिकों ने अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के पुरस्कार से उनका मनोबल बढ़ा है एवं उन्हें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कर्म शिरोमणि एवं पाली शिरोमणि पुरस्कार अपने कार्यस्थल में नवीनता, बेहतर संसाधनों का उपयोग एवं संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने, सुरक्षा के मानक मापदण्डों के साथ विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिया जाता है। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी श्री जसबीर सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री राजेश बाबु एवं श्री भुवन साहू का सराहनीय योगदान रहा।

जीपीएफ खातों की त्रुटि निराकरण के लिए 4 दिवसीय शिविर शुरू

महासमुंद। ज़िले के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खातों में त्रुटियों के निराकरण एवं संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आज सोमवार 1 मई से चार दिवसीय शिविर जिला कोषालय महासमुंद में शुरू हो गया। महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारी शिविर में रहकर जीपीएफ़ त्रुटि संबंधी समस्याओं का निराकरण कर रहे है। यह शिविर गुरुवार 4 मई चलेगा।

ज़िला कोषालय अधिकारी श्री डी.पी.वर्मा ने बताया कि आज पहले दिन महासमुंद ब्लॉक के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खातों में त्रुटियों के निराकरण 18 प्रकरण आए जिसमें 15 प्रकरण पंजीबद्ध किए 3 प्रकरण में संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने कहा गया। कल मंगलवार 2 मई को उप कोषालय सरायपाली से संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में त्रुटियों के प्रकरणों के निराकरण किया जाएगा। वही 3 मई को उप कोषालय पिथौरा और 4 मई को उप कोषालय बागबाहरा विकासखंड के के अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय में आकर कर्मचारियों की जीपीएफ़ त्रुटियाँ दूर करा सकते है। उन्होंने सभी डीडीओ से अपील की कि वे शिविर में अकार अपने कर्मचारियों की जीपीएफ़ त्रुटि संबंधी समस्याओं का निराकरण करायें। जिले के कर्मचारियों से अपील की है त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में उपस्थित होकर निराकरण करवा सकते है। यदि किसी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो वे त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में उपस्थित होकर निराकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि त्रुटि सुधार के लिए दस्तावेज संबंधित डीडीओ से सत्यापित होना अनिवार्य है। यह चार दिवसीय शिविर पूर्वाह्न 11:00 बजे से आयोजित होता है।

बासागुड़ा के जंगल से तीन नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सारकेगुड़ा से थाना बासागुड़ा और कोबरा 210 की संयुक्त टीम आउटपल्ली, साकेगुड़ा, कोरसागुड़ा की ओर एवं केरिपु 168/जी की टीम राजपेंटा की ओर एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी।

अभियान के दौरान बासागुड़ा के जंगल से 2 संदिग्ध को पकड़ा उनसे पूछताछ करने पर कट्टम धुर्वा एरिया कमेटी अंतर्गत आर्थिक शाखा अध्यक्ष निवासी ग्राम आउटपल्ली थाना तर्रेम, राजू पदम सप्लाई टीम सदस्य, छात्र संगठन का सदस्य निवासी कोरसागुड़ा थाना तर्रेम जिला बीजापुर होना बताया। जिनके पास रखे थैला की तलाशी लेने पर पर्चे एवं बैनर बरामद किया गया। कट्टम धुर्वा थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत 18 जनवरी 2019 को बासागुड़ा-सारकेगुड़ा मार्ग पर राजपेंटा के पास आईईडी लगाने की घटना में शामिल था। 12 जनवरी 2021 को कोरसागुड़ा ग्रामीणों से अपहरण एवं मारपीट करने, 26 अप्रैल 2023 को बासागुड़ा-आवापल्ली मार्ग पर गौठान के पास शासन विरोधी पर्चा, बैनर लगाने की घटना में शामिल था। इसके विरूद्ध थाना बासागुड़ा में 2 स्थाई वारंट लंबित है। वापसी के दौरान राजपेंटा के जंगलों से 1 संदिग्ध को पकड़ा गया पुछताछ करने पर पदम विमलेश निवासी कोर्रेसागुड़ा थाना तर्रेम को पकड़ा गया जिसके पास रखे थैला से पर्चा एवं बैनर बरामद किया गया। गिरफ्तार तीनों नक्सलियों के विरूद्ध थाना बासागुड़ा में कार्यवाही उपरान्त न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया।

नक्सलियों के परतापुर एरिया कमेटी ने टांगा संगम में बैनर

कांकेर। ग्राम संगम में नक्सलियों के परतापुर एरिया कमेटी ने बैनर टांग कर बैनर में लिखा है, कि अंजाडी के मानू धुरवा को जन अदालत में दी गई मौत की सजा पर झूठे बयान के आधार पर एफआईआर वापस लेने एवं इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को पुलिस वालों से सावधान रहने तथा पुलिस के लालच में नही आने की बात बैनर में लिखी गई है। गौरतलब है कि जिले के ग्राम संगम में लगाये गये नक्सली बैनर में जिस ग्राम अंजाडी का जिक्र किया गया है, वह मौके से 4.10 किमी की दूरी पर स्थित है।

दीपका-हरदीबाजार बायपास खस्ताहाल को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया चक्का जाम

कोरबा। कारण चाहे जो भी होए करोड़ों की लागत से बनाया गया दीपका. हरदीबाजार बायपास की दुर्गति हो गयी है। जहां.तहां गड्डों की मौजूदगी के कारण आवागमन बाधित हो गया है। वर्षो में किया गया था। इससे पहले दीपका से हरदी बाजार जाने के लिए एकमात्र रास्ता था और उस पर कोयला से लेकर अन्य वाहनों की आवाजाही हो रही थी। असुविधा और हादसों के

इसके चलते आम जनता मुश्किल में है। इस मसले को लेकर दीपिका चौराहे पर आज यूथ कांग्रेस के द्वारा चक्का जाम कर नाराजगी जाहिर की गई।

बायपास की बदहाली को लेकर अलग अलग तरीके से ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की लागत से दीपिका हरदी बाजार बाईपास का निर्माण हाल के सिलसिले को लेकर बाईपास से की जरूरत महसूस की गई और इस दिशा में काम किया गया। कोरबा के एक ठेकेदार के द्वारा इसका काम कराया गया जिस पर कई करोड़ रुपए खर्च की गई। निगरानी के अभाव में गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ा और थोड़े समय के बाद ही इसने अपनी असलियत दिखा दी। पूरे बाईपास में जहां.तहां गड्ढे ही गड्ढे नजर आए हैं और इनकी वजह से इस रास्ते पर छोटे-बड़े वाहनों को ना केवल चलने में असुविधा हो रही है बल्कि आए दिन वे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इससे चालकों के साथ-साथ आम लोग बेहद परेशान हैं। अपनी अपनी जानकारी हिसाब से लोग इस मामले में नाराजगी जताने की कोशिश कर रहे हैं। दीपिका थाना चौराहे के पास इसी मुद्दे पर आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में वाहनों की लंबी लाइन लग गई और एक बार फिर आवाजाही करने वालों के सामने परेशानियां आयी।

याद रहे भारी वाहनों की आवाजाही को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए कोयला कंपनी के द्वारा एक अलग बाईपास बनाया गया है जो कोयला वाहनों के लिए निर्धारित है। इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर हायतौबा कायम है। जबकि एक अन्य मार्ग को तैयार कराया गया है। उसे चौड़ा करने की मांग की जा रही है। रास्ते के संकुचित होने से आए दिन यहां वाहनों का जाम लग रहा है और मुश्किलें बढ़ रही है।

कांग्रेस नेता और आईपीएस अफसर के बीच हाथापाई

बस्तर कोतवाली के अंदर चले थप्पड़, कार्यकर्ताओं का हंगामा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मंगलवार को कांग्रेस नेता और ट्रेनी आईपीएस के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान थाने में जमकर थप्पड़ चले। इसका पता चलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्र हो गए और थाने में जमकर हंगामा किया। इसके बाद कार्यकर्ता एसपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक कांग्रेस कार्यकर्ता किसी काम से बस्तर कोतवाली पहुंचे थे। इसी दौरान उनका ट्रेनी आईपीएस से विवाद हो गया। इसके बाद से अभी तक हंगामा जारी है।

जानकारी के मुताबिक, युवक कांग्रेस के एक नेता मंगलवार को किसी मामले के सिलसिले में सिटी कोतवाली पहुंचे थे। उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कांग्रेस नेता का प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार से विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ओर से धक्कामुक्की होने लगी और बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि अफसर ने कांग्रेस नेता को थप्पड़ मारे। वहीं जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली के अंदर घुस गए और हंगामा कर दिया।

इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता वहां से निकले और एसपी दफ्तर पहुंच गए। फिलहाल एसपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसमें शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, विधायक रेखचंद जैन भी एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। यहां नेताओं और अफसरों के बीच बातचीत जारी है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

कहा मान बढ़ाया आपने आपका आभार, खुशी से थिरका तन और मन

रायपुर। स्वास्थ्य और शिक्षा में अमूल्य योगदान देने वाली आंगनबाड़ी बहनें और मितानिनों की खुशी आज देखते ही बन रही थी। साइंस कॉलेज मैदान में आभार उत्सव में इन बहनों ने नृत्य के जरिए जमकर अपनी खुशी व्यक्त की। खुशी से थिरकते इन बहनों ने कहा मान बढ़ाया आपने आपका आभार, छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार।

राज्य के हर कोने से आयी हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा मानदेय बढ़ाने की खुशी सब में दिख रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुश्री साधना देवांगन ने आभार जताते हुए कहा कि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जब सेवानिवृत्त होते थे तो सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिलता था। परंतु अब सेवानिवृत्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50 हजार रुपए तथा सहायिका को 25 हजार रुपए की राशि मिलेगी। बाइस सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम कर रही दुर्ग की श्रीमती प्रभा कुठारे कहती है कि घर की स्थिति ठीक नहीं थी मानदेय से ही वो घर चलाती हैं पर दिनों दिन मंहगाई बढ़ने से उन्हें

काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में जब मानदेय बढ़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

भाठागांव रायपुर की मितानिन श्रीमती लक्ष्मी साहू ने कहा कि मानदेय बढ़ाने की घोषणा सुनकर, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि यह हो सकता है। मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण था। बस्तर से आई मितानिन श्रीमती प्रेम ज्योति बघेल ने हल्बी में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कड़ी मेहनत करती हूं। उनके गांव में साढ़े 3 सौ लोग हैं। यहां गर्भवती माताओं को देखती हूँ। साथ ही सामान्य बीमारियों में जरूरत पड़ने वाली दवाई देती हूँ। अब 2200 मानदेय दिया है तो 7 हजार रुपये तक महीना कमा लुंगी। अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी।

गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय की राशि 6500 रुपये बढ़ाकर 10 हजार रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3250 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत बहनें लाभांवित होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मितानिन बहनों के योगदान देखते हुए को राज्य मद से 2,200 रूपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है।

अब आरक्षण पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला तेज

रायपुर. बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए तत्कालीन सरकार के 58 फीसदी आरक्षण के फैसले को सही बताया है. इस फैसले के बाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब भाजपा का कांग्रेस पर हमला तेज हो गया है. भाजपा नेता विक्रम उसेंडी ने कहा कि इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के 58 प्रतिशत आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस की दोहरी राजनीति का पर्दाफाश हुआ है. बीजेपी शासन काल में लागू आदिवासियों के 32ब आरक्षण पर कांग्रेसियों ने षड्यंत्र कर हाईकोर्ट में याचिका लगवाकर स्टे लगवा दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण संशोधन विधेयक 2012 पर लगे स्टे पर राहत दे दी है. अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान से ऊपर नहीं हैं.

विक्रम उसेंडी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप

विक्रम उसेंडी ने कहा कि यह सभी को मालूम है कि जिन लोगों ने 58ब आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, कांग्रेस की सरकार ने ऐसे लोगों को निगम आयोग मंडल के पद से सुशोभित किया है. यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कहने पर ही उनके लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी. सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने ऐसे लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने वाले पदों पर बैठाया.

भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

भाजपा नेता विक्रम उसेंडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले न्याय से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट तक में शासन ने अपना पक्ष बेहतर नहीं रखा. कांग्रेस चाह रही थी कि सरकार किसी तरह हार जाए, इसीलिए उसने क्रांटिफायबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया है. ऐसे तमाम कृत्यों के कारण कांग्रेस की नीयत पर हमेशा सवाल उठता ही रहेगा

भर्तियां शुरु करने की मांग = भाजपा ने यह आरोप भी लगाया है कि रमन सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू किया लेकिन कांग्रेस ने उसे छीना. फिर बीजेपी ने संघर्ष कर सरकार के खिलाफ चक्काजाम, धरना और हर संभव प्रयास कर आरक्षण लागू करवाया है.

छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण मिलता रहे, पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है. भाजपा ने 58 फीसदी आरक्षण से स्टे हटने पर अब सरकार से भर्ती करने की मांग की है. बीजेपी ने जल्द से जल्द खाली पदों पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर लागू कर भर्तियां शुरु करने को कहा है.

भाजपा की लापरवाही से आरक्षण कम हुआ था कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल करवाया - कांग्रेस

रायपुर। भाजपा का यह कहना कि 58 प्रतिशत आरक्षण की बहाली उसकी विचारो की जीत है हास्यास्पद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि दरअसल 58 प्रतिशत आरक्षण भाजपा की रमन सरकार की जानबूझकर बरती गयी लापरवाही से ही अदालत में खारिज हुआ था। मुकदमे के शुरूआती 6 सालों तक रमन सरकार जानबूझकर तथ्य अदालत से छुपाते रही रमन सरकार के समय सन् 2012 में 58 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा लगा था। जिसके संबंध में तत्कालीन रमन सरकार अदालत में सही तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाई रमन सरकार की लापरवाही से ही अदालत का फैसला 58 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफआया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी वहां पर देश के सबसे ख्यातिनाम तीन वकीलों मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनुसिंघवी को पैरवी के लिये रखकर अपना पक्ष रखा जिसके कारण 58 प्रतिशत आरक्षण फिर से बहाल हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण रद्द किये जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने एक ओर जहां बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया दूसरी ओर विधानसभा से विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाया विधानसभा में पारित विधेयक में 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसमें कांग्रेस सरकार ने सर्व समाज को आरक्षण देने विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवा कर राजभवन भेजा है। भाजपा के षड्यंत्रों के कारण उस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को उनकी जनगणना के आधार पर तथा पिछड़ा वर्ग को क्रांटो फायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

बाबू भैया की कलम से

साय प्रकरण; राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं

राजनीति के क्षेत्र का एक बड़ा नाम नंद कुमार साय अब अपने नए घर में प्रवेश कर गए हैं। पुराना घर उन्हें अब खंडहर सा लगने लगा था। उनकी कल्पना के भूत उन्हें वहां डराने लगे थे। वहां उनका दम घुटने लगा था। घुटेगा भी क्यों नहीं , जब तक ताजपोशी रही तब तक ये भूत अँधेरों में छुपे रहे। सामने आने की हिम्मत नहीं की। तब सताने का तो प्रश्न ही नहीं था। अब कुर्सी खाली है, तो कथित भूत उनका अपमान करने लगे। उनके राजनैतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा कर उन्हें परेशान करने लगे। बड़े मंच पर बिना सलाह मशविरे , राजनीति के उनकी तुलना में एक नाटे कद के नेता ने कह दिया कि जब तक कांग्रेस को सरकार से हटा नहीं देंगें, तब तक साय बाल नहीं कटाएंगें। बुरा तो लगना ही था। हमारे प्यारे दुलारे बालों को बलि चढ़ाने वाले तुम कौन हो भाई ? समझ गए यह उनसे पूछे बिना घोषणा किया जाना अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें नीचा दिखाने का व अपमान करने का प्रयास है। पार्टी के कद्दावर नेता थे नंदकुमार साय। लंबे समय से खाली बैठे थे। पार्टी में कोई तवज्जो नहीं। बैठकों में बुलावा नहीं। कोई सुझाव सलाह नहीं। सोचिए अटल बिहारी बाजपेयी जैसे कद्दावर नेता के साथ सहज काम करने वाले किसी नेता की यह हालत हो जाये तो वो क्या सोचेगा ? और आखिर करेगा क्या ? हर कोई आडवाणी-मुरली मनोहर नहीं हो सकते। डॉ.रमनसिंह सरकार के कार्यकाल में अपनी घोर उपेक्षा के कारण यदा कदा पार्टी को आंख दिखाने वाले बयान देकर ही संतुष्टि करनी पड़ती थी। सनसनी फैलती थी मान मनौवल के बाद राजनीतिक तूफान शांत हो जाता था। यह भी सच है कि वे मान भी जल्दी जाते थे। वे गांव गरीब व आदिवासियों के हित की राजनीति को ही असल जनसेवा मानते हैं। अब आरएसएस व भाजपा के बाद घोर विरोधी पार्टी रही कांग्रेस में आ गए तो अपनी व्यथा बताने के साथ जो बात कही वह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह कहा कि वे मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के लिए किये जा रहे कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। नरवा-गरुवा-घुरूवा-बाड़ी जैसी ग्रामीणों की सेवा की कल्पना के कायल हैं। इसीलिए वे जनसेवा के लिए भूपेश का नेतृत्व स्वीकार रहे हैं। पूरा जीवन आरएसएस व भाजपा जैसी अपने सिद्धांतों व नीतियों से समझौता नहीं करने वाली संस्थाओं से निष्ठा के साथ जुड़े रहे। उनका मोहभंग कोई तात्कालिक घटना नहीं है ,निश्चित रूप से लंबी सोच विचार के बाद लिया गया गंभीर निर्णय है। यही कारण है कि जब डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा के दिग्गज उनके निवास के द्वार पर पहुंचे तो साय के परिवार ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। साय से किसी की बात नहीं कराई। साफ है कि घर बदलने का निर्णय पक्का था,उसमें कोई फेरबदल करने व भावनाओं का आधार शेष नहीं था। लगता है इतना अपमान महसूस किया गया था कि उन्हें इस दौर में भाजपा द्वारा उनको समय समय पर विधायक,सांसद,राज्यसभा सांसद, अविभाजित मध्यप्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही विषम परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ का प्रथम नेता प्रतिपक्ष बनाये जाने का एहसान भी याद नहीं आया। वर्तमान अपमान के घाव का दर्द कुछ ज्यादा ही भारी पड़ा। इतना भारी की पुराने घर की दीवारें भी उनको सताने व डराने लगी। घर भी जेल के विशेष सेल की तरह डरावना लगा। दम घुटने लगा तत्काल ताजी हवा की जरूरत महसूस हुई। हल ढूंढना शुरू हुआ। राजनीति का ऑक्सीजन दिल्ली जाने पर मिला,रास्ता बना। जब तक पुराने घर के साथी कुछ समझ पाएं,अचानक धमाका कर दिया। कल तक जिसे कोसते रहे उसका दामन थाम लिया। सही कहा है राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजनीति ही एकमात्र मंच है जहां विरोधी भी दोस्त होते हैं। दुश्मन भी अगले ही क्षण दोस्त हो सकते हैं। यहाँ वोट की स्वार्थी राजनीति को प्राथमिकता में रखा जाता है। बाकी सब कृत्य दूध- भात होता है। इसी राजनीति में नंदकुमार साय को अपने साथ जोड़ कर भूपेश बघेल ने सटीक दांव खेल कर बहती नदी की धारा के रुख को पलटने का काम किया है। भाजपा इस दांव से हतप्रभ हुई है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। भविष्य में आदिवासी राजनीति में नया परिवर्तन दिखाई दे सकता है। कांग्रेस के लिए कल का दिन दोनों हाथ में लड्डू जैसा प्रसंग रहा है। एक तो आदिवासी कद्दावर नेता साथ आये ,दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की रोक को बहाल कर दिया। इन दोनों लड्डुओं की कितनी मिठास कांग्रेस के चुनावी दौर में घुलेगी यह देखने की बात है।चुनावी दौर की उलट पलट में और कौन कौन दोस्त-दुश्मन का खेल खलेंगें यह देखना है। देखें आगे आगे होता है क्या ?

समन पर ईडी कार्यालय पहुंचे रायपुर महापौर एजाज ढेबर, अधिकारी कर रहे पूछताछ

रायपुर। नगर निगम महापौर एजाज ढेबर प्रवर्तन निदेशालय के समन पर मंगलवार को पचपेड़ी नाका स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे लंबी पूछताछ चली. इसके पहले 29 मार्च को महापौर एजाज ढेबर के घर पर ईडी ने छापा मारा था. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ईडी की ओर से की गई उस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं. उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ही महापौर एजाज ढेबर से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं.

महापौर एजाज ढेबर के ईडी दफ्तर पहुंचने की खबर मिलने के बाद उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे. पचपेड़ी नाका स्थित ईडी के उप क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर समर्थकों ने महापौर एजाज ढेबर के समर्थन जमकर नारेबाजी की. साथ ही केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ भी नारे लगाए.

बैंड बजा लेकर पहुचे समर्थक- महापौर के ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने ईडी कार्यालय का घेराव किया. कार्यालय के बाहर जहां एक और समर्थक महापौर के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं तो वहीं ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं. समर्थकों ने ईडी दफ्तर में घुसने की भी कोशिश की लेकिन गेट बंद होने और पुलिस बल लगे होने के चलते उनकी कोशिश नाकाम रही. एक दिन पहले महापौर ने समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया. इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ नालों में उतर कर नाले की सफाई की. इसके बाद अपने समर्थकों के साथ शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर जन्मदिन मनाया. बताया जा रहा है कि मार्च में एजाज ढेबर के घर पर पड़े छापे में ईडी की टीम को कुछ सबूत मिले हैं, इस बारे में महापौर से पूछताछ की गई। हालांकि पहले भी महापौर कह चुके हैं कि ईडी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। पिछली बार जब ईडी ने रायपुर महापौर एजाज ढेबर के घर पर छापा मारा था तो उन्होने अफसरों पर परेशान करने का आरोप लगाया था।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस के गुंडाराज में विधायक बैंक कर्मियों और कार्यकर्ता आईपीएस को पीट रहे- केदार

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता सुशील मौर्य द्वारा थाने में आईपीएस अधिकारी सीएसपी विकास कुमार के साथ हाथापाई और उसके बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा आईपीएस अधिकारी पर ही माफी मांगने का दबाव बनाने का हवाला देते हुए कहा है कि भूपेश बघेल के राज में कानून व्यवस्था का यह हाल है कि कांग्रेस के विधायक बैंक कर्मचारियों को पीट रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कानून के रखवाले पुलिस अफसरों को थाने में घुसकर पीट रहे हैं। यह लोकतंत्र का कानून का राज है या कांग्रेस का आतंकराज! प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गुंडाराज चला रही है। ये कांग्रेस के गुंडे जब सरकारी सेवकों और भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों पर बेझिझक हाथ उठा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्हें गुंडागर्दी की खुली छूट दे रखी है। प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जब सरगुजा में कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने बैंक कर्मचारियों को पीटा तो मुख्यमंत्री की गैरजिम्मेदाराना प्रतिक्रिया आई कि आपस का मामला है।

खुलकर सामने आ गया कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा - बृजमोहन

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल और पर प्रतिबंध लगाने के वादे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पीएफआई पर केंद्र सरकार टेरर फंडिंग उजागर होने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। देश की कई आतंकी गतिविधियों में पीएफआई की संलिप्तता जग जाहिर है बावजूद कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए इस आतंकी संगठन की तुलना धार्मिक संगठन बजरंग दल से करते हुए प्रतिबंध की बात कही है। बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति में इतनी आगे बढ़ गई है कि वह सनातन हिंदू धर्म को दोयम दर्जे पर रखती है। देश की तरह कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भी तुष्टिकरण और धर्मांतरण के एजेंडे पर काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ में हिन्दू संगठनों को प्रताड़ित कर तुष्टिकरण में व्यस्त कांग्रेस सरकार धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले उनके नाम पर दिखावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बजरंगबली के भक्तों का दमन कर ही रहे हैं और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा कर दिया है।

आरडीए संचालक मंडल का हीरापुर योजना का दौरा

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल के सदस्यों मे आज प्राधिकरण की डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना हीरापुर का दौरा किया। इस अवसर उन्होंने निवासियो की साफ ड्रू सफाई, नालियों के टूटफूट फ्लैट्स के रखरखाव और नालियों से संबंधित शिकायतों का अवलोकन किया।

प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा, श्री शिव सिंह ठाकुर संचालक मंडल के संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्री हिरेद्र देवांगन, और श्रीमती चन्द्रवती साहू से वहां के निवासियों ने कहा कि नियमित रुप से सफाई ठेकेदार के लोग काम करें इस बात के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। प्राधिकरण व्दारा योजना में रिक्त फ्लैट्स जिन्हें विक्रय किया जाना है उसकी मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। संचालक मंडल के सदस्यों ने योजना में बने शॉपिंग कॉम्पलेक्स में व्यावसायियों व वहां आने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए टॉयलेट ब्लॉक के जीर्णोव्दार के बाद उसे व्यवसायियों को सौंपा गया। इस अवसर पर क्षेत्र के व्यवसायी रितेश सिंह, बबलू केसरवानी, सी.एल.साहू, विकास केसरवानी, निवासियो में दर्शन कौर भामरा, मोहम्मद साजिद सहित प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता श्री अनिल गुप्ता, कार्यपालन अभियंता श्री आर.के. जैन, सहायक अभियंता विवेक सिन्हा, उप अभियंता दिग्विजय साहू उपस्थित थे।

मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए रेलवे खानपान सेवा ठेकेदारी कर्मचारी कल्याण संघ ने श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा

रायपुर। रेलवे खानपान सेवा ठेकादारी कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा अपने सदस्यों के मूलभूत सुविधाओं के संबंध में क्षेत्रीय श्रमायुक्त केन्द्रीय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर लंबी सुनवाई के पश्चात विगत दिनांक 19/04/23 को रेलवे स्टेशन रायपुर में कार्य करने वाले वेंडरो को क्षेत्रीय श्रमायुक्त केन्द्रीय रायपुर के द्वारा वर्कमेन मानते हुए रेलवे एवं ठेकेदार के विरुद्ध इन्डस्ट्री डिस्पुट का प्रकरण दर्ज किया गया था जिस पर आज दिनांक 02/05/23 पुन: श्रमायुक्त महोदय केन्द्रीय के समक्ष रेलवे खानपान सेवा ठेकादारी कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिक्षण करने के पश्चात श्रमायुक्त महोदय केन्द्रीय रायपुर के द्वारा रेलवे एवं खानपान ठेकेदार से आगामी सुनवाई की तिथि में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है.विशेष उल्लेखनीय है कि वर्षों से रेलवे स्टेशन रायपुर के में काम करने वाले सैकड़ों वेंडरो को आज तक किसी भी विभाग ने कर्मचारी (वर्कमेन) नहीं माना था रेलवे खानपान सेवा ठेकादारी कर्मचारी कल्याण के द्वारा काफी लंबा संघर्ष किया गया तब जाकर हमें यह पहचान मिल पाई है. रेलवे खानपान सेवा ठेकादारी कर्मचारी कल्याण संघ के समस्त सदस्य श्रमायुक्त महोदय केन्द्रीय रायपुर का तहेदिल से आभार व्यक्त करते हैं।

ग्राम पटेल, कोटवार और होमगार्ड का आभार सम्मेलन आज साइंस कॉलेज मैदान में

रायपुर। राजधानी स्थित साइंस कॉलेज मैदान में बुधवार 3 मई को सुबह 11 बजे ग्राम पटेल, कोटवार और होमगार्ड का आभार सम्मेलन एवं ग्राम गौठान प्रबंधन समिति सदस्यों का सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल होंगे। सम्मेलन में कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, राजस्व एवं आपदा मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, वाणिज्य मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, लोक स्वास्थ्य मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल समेत संसदीय सचिव श्री इंद्रशाह मंडावी, सुश्री शकुंतला साहू, श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर श्री एजाज ढेबर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत डॉ. रामसुंदर दास एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

डाटा कलेक्शन के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी को मिली राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

रायपुर। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में शहर विकास और जन सुविधाओं से संबंधित आँकड़े के बेहतर व उपयोगी संकलन के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है । उन्होंने इस आशय का प्रशंसा पत्र रायपुर स्मार्ट सिटी के एम डी श्री मयंक चतुर्वेदी को प्रेषित किया है , साथ ही चंडीगढ़ में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्य परिचालन अधिकारी श्री उज्जवल पोरवाल रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए उनके हाथों सम्मानित भी किए गए।इन उपलब्ध आँकड़ों के समुचित उपयोग से नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लागू किए जाने वाले नवाचारों का क्रियान्वयन सुगम हो सकेगा ।

रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा बुनियादी जन सुविधाओं के उपयोग संबंधी ये आँकड़े एकत्र कर इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत सरकार को उपलब्ध कराए गए थे । इन आँकड़ों का उपयोग नागरिक सुविधाओं को विस्तारित करने संचालित होने वाले नवाचारों में होगा ।

- चंडीगढ़ में रायपुर हुआ सम्मानित
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री कुणाल कुमार ने की प्रशंसा
- नवाचारों में उपयोगी होंगे रायपुर के आँकड़े

रायपुर स्मार्ट सिटी ने ये डाटा नगर निगम, स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट के साथ ही सुविधाओं और जन सेवा के लिए कार्य कर रहे अन्य शासकीय विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों व कार्ययोजनाओं से संबंधित हैं , जिसका समुचित लाभ आम नागरिकों को सुगमता पूर्वक प्राप्त हो रहा है । रायपुर स्मार्ट सिटी ने विभिन्न विभागों से समन्वय कर संबंधित डाटा संकलन उपरांत भारत सरकार को उपलब्ध कराये गए थे ।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव व स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर श्री कुणाल कुमार एवं भारत सरकार के इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम के सीईओ डॉ. इंदर गोपाल ने इन आँकड़ों को नवाचारों के लिए उपयुक्त आँकड़े मानते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के प्रयासों को सराहा है ।

छत्तीसगढ़ में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संचालित की जा रही है सिल्क समग्र योजना

रायपुर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रेशम पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में इसके लिए सिल्क समग्र योजना-2 शुरू की गई है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के 14 जिलों के रेशम अधिकारियों के तकनीकी ज्ञनयन के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड बेंगलूरू और ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

एक मई से शुरू हुए प्रशिक्षण में अधिकारियों को किसानों को सहायता, कृषकों को प्रशिक्षण, विस्तार प्रबंधन, रेशम उत्पादन एवं व्यावसायिक उद्देश्य, क्लस्टर एप्रोच, शहतूती पौधों का विकास एवं प्रबंधन, रेशम विस्तार कृषकों के यहां बुनियादी सुविधाओं का विकास, अधोसंरचनाओं का निर्माण, शहतूत पौधों के रोग एवं कीट प्रबंधन, रेशम कीट पालन प्रबंधन एवं सावधानियां की जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण में जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव जिलों से जिला अधिकारी एवं प्रक्षेत्र अधिकारी शामिल हैं।

प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर संचालक ग्रामोद्योग श्री अरूण प्रसाद पी0 और अपर संचालक डॉ0 राजेश बघेल, ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए रेशम विकास एवं विस्तार को प्रथम प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशिक्षण में कृषकों को दी जाने वाली वित्तीय एवं तकनीकी सुविधायें तथा राज्य सरकार के द्वारा कृषकों के हित में दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं की जानकारी दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.